

[2023] 8 एस. सी. आर 969

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी।

बी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्या

(सिविल अपील सं। 1144-1146 2011 का)

12 अप्रैल, 2023

[एम. आर. शाह और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894। 4 (1) , 6 , 44 बी-भूमि अधिग्रहण नियम, 1963-आरआर। 3
& 4 - अधिग्रहण कार्यवाही निजी कंपनी की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

विश्वविद्यालय कंपनी के प्रति अनुचित पक्षपात-अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करना-सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत-का उल्लंघन-अपीलार्थी, उस समय की एक निजी कंपनी, ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भूमि देने के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया-सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए-हालांकि, कानून

वेदांता फाउंडेशन द्वारा और उसके बाद अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा, जो स्वीकार्य रूप से प्रासंगिक समय पर और 19.07.2006 पर एक निजी कंपनी थी-यह अपीलार्थी का मामला था कि यह सफलतापूर्वक 23.11.2006 पर सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो गई और इसने सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 44 ने शेयरों की मुफ्त हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध को हटाने के लिए अपने संघ के लेखों में संशोधन किया और इसे कंपनी पंजीयक (आरओसी) द्वारा दिनांक 21.02.2007 की स्वीकृति द्वारा स्वीकार किया गया है और

03.03.2011 - हालाँकि, बाद की स्वीकृति भी

[2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21.02.2007 और 03.03.2011 पर कंपनियों का पंजीयक था एस के बहुत बाद। 4 (1) अधिसूचना जो 13.12.2006 से 21.08.2007 के बीच जारी की गई थी-इसलिए, कानूनी रूप से, अपीलार्थी को प्रासंगिक समय पर सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित नहीं किया गया था-प्रासंगिक समय पर, जब कंपनी एक निजी कंपनी थी, एस के तहत प्रतिबंध को देखते हुए। 44

1894 के अधिनियम के बी, विचाराधीन भूमि को अपीलकर्ता कंपनी द्वारा अधिग्रहित करने की मांग नहीं की जा सकती थी-निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में बाद में रूपांतरण अधिनियम, 1894 के तहत वैधानिक प्रावधान से बाहर निकलने का एक प्रयास था, जो अपीलकर्ताओं की ओर से दुर्भावनापूर्ण अभ्यास है।

आर. आर. के तहत अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन। 3 और नियमों के 4,

1963 और इसलिए, लाभार्थी कंपनी के लिए पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को दूषित कर दिया गया था-पर्यावरणीय पहलुओं और विचाराधीन अधिग्रहित भूमि से दो नदियों के गुजरने पर भी राज्य सरकार द्वारा दिमाग का उपयोग नहीं किया गया था-नदियों आदि का रखरखाव लाभार्थी कंपनी को कैसे सौंपा जा सकता है-यदि विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण लाभार्थी कंपनी द्वारा जारी रखा जाता है, तो नदियों का नियंत्रण लाभार्थी कंपनी के पास होगा।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए सड़क और अधिग्रहित भूमि इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण से वन्यजीव अभयारण्य, संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली और पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इलाके में वातावरण-अन्यथा भी, लाभार्थी कंपनी द्वारा भूमि की आवश्यकता पर राज्य सरकार की ओर से कोई आवेदन नहीं है-अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, यह प्रतीत होता है कि अनुचित लाभ प्रस्तावित किए गए थे/वास्तव में प्रस्तावित किए गए थे और लाभार्थी कंपनी को अनुचित उदारता प्रदान करने के लिए दिए गए थे-यह सराहनीय नहीं है कि सरकार ने एक न्यास को इस तरह के अनुचित अनुग्रह की पेशकश क्यों की /

कंपनी-इस प्रकार, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही और लाभ,

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पक्षपात और कला के उल्लंघन से दूषित हो गए थे। 14 संविधान के अनुसार-उच्च न्यायालय ने पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दरकिनार कर दिया, जो अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 के तहत वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से दूषित हो गई थी और दुर्भावना और पक्षपात से भी दूषित हो गई थी।

और प्रासंगिक पहलुओं पर मन के गैर-अनुप्रयोग का एक स्पष्ट मामला है

भारत का संविधान-कला। 14 .

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. अधिग्रहण की प्रक्रिया की शुरुआत वेदांत फाउंडेशन और उसके बाद अनिल अग्रवाल ने की थी। फाउंडेशन, जो निश्चित रूप से प्रासंगिक समय पर और 19.07.2006 पर एक निजी कंपनी थी, जिसके बोर्ड में तीन निदेशक थे और सात से कम सदस्य थे। द्वारा चिन्हित की गई चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की शुरुआत

अपीलकर्ता कंपनी अप्रैल/जून, 2006 के महीने में थी, जिसके बाद 19.07.2006 दिनांकित समझौता ज्ञापन हुआ। इसलिए,

विचार के लिए प्रासंगिक तिथि 19.07.2006 होगी न कि 13.12.2006 जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए। [पैरा 8.5] [1014-एफ-जी, एच; 1015-ए]

1.2 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अन्यथा भी बाद में निजी से कथित धर्मांतरण

कंपनी से सार्वजनिक कंपनी से बाहर निकलने का प्रयास था

अधिनियम, 1894 के तहत वैधानिक प्रावधान। विधि विभाग ने विशेष रूप से कहा कि निजी कंपनी द्वारा भूमि का अधिग्रहण उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए भूमि की मांग की गई थी।

अधिग्रहण के बाद ही अपीलकर्ताओं ने कंपनी की स्थिति को निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया। उपरोक्त अपीलार्थियों की ओर से एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास था।

[पैरा 8.6] [1015-बी-सी]

03.03.2011 संबंधित है, यह नोट किया जाना आवश्यक है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विचार के लिए प्रासंगिक तिथि जून, 2006 होगी और किसी भी मामले में 19.07.2006 जब समझौता ज्ञापन किया गया था। यहां तक कि आरओसी द्वारा बाद की स्वीकृति धारा 4 (1) अधिसूचना के काफी बाद भी 21.02.2007 और 03.03.2011 पर थी। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया और कानूनी रूप से अभिनिर्धारित किया गया, अपीलार्थी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित नहीं किया गया था। जो कि एक धारा 25 कंपनी थी और इसलिए, एक सार्वजनिक कंपनी नहीं थी। [पैरा 8.7] [1015-डी-जी] [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्कर्ष दिए हैं कि नियम, 1963 के नियम 3 और 4 के तहत अनिवार्य प्रावधानों का गैर-अनुपालन है और इसलिए, लाभार्थी कंपनी के लिए पूरी अधिग्रहण कार्यवाही है। दूषित किया गया है और नियंत्रण और संतुलन हैं और कुछ अनिवार्य प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है, विशेष रूप से, जब कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, तो इसका पालन करना होगा और संबंधित पहलुओं पर विचार नहीं करना होगा, जिन पर नियम 4 के तहत विचार करना अनिवार्य है, जिससे पूरी अधिग्रहण कार्यवाही दूषित हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि को प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं करने पर दूषित कर दिया गया है, विशेष रूप से,

नियम 4 में उल्लिखित पहलू। [पैरा 8.15] [1021-सी-डी] 3. सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है पर्यावरण के पहलुओं पर राज्य सरकार द्वारा दिमाग का उपयोग न करना और नदी से दो नदियों का गुजरना।

विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण। यह विवाद में नहीं है कि विचाराधीन भूमि से दो नदियाँ 'नुआनई' और 'नाला' बह रही हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया था। नदियों आदि के रखरखाव को कैसे सौंपा जा सकता है

लाभार्थी कंपनी। यदि विचाराधीन भूमि बनी रहती है

लाभार्थी कंपनी द्वारा अधिग्रहित नदियों का नियंत्रण उक्त निजी कंपनी के पास होगा, जो सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा। यहाँ तक कि लाभार्थी कंपनी की आवश्यकता भी

उपरोक्त दो नदियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए इलाके के निवासियों को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जा सकता है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सड़क के ठीक पार, एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय और अधिग्रहित भूमि के लिए सड़क के ठीक बगल में है। इसलिए, उच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण से वन्यजीव अभयारण्य, संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली और इलाके के पारिस्थितिक पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्यजीव अभयारण्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और इलाके के पारिस्थितिक पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित वेदांत विश्वविद्यालय से समुद्र की दूरी भी लगभग 2000 मीटर है। केवल इसलिए कि बालूखंड वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित स्थल से एक राजमार्ग-पुरी-कोणार्क मरीन ड्राइव द्वारा अलग किया गया है, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. के लिए विशाल भूमि का अधिग्रहण करने का आधार नहीं हो सकता है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, यह वन्यजीव अभयारण्य और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। इलाका अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत प्रस्ताव और/या आपत्तियों पर विचार करते समय भी राज्य सरकार और/या कलेक्टर और/या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। [पैरा 8.17 और 8.18] [1022-एफ-एच; 1023-ए-डी]

4. अन्यथा भी, की ओर से एक गैर-आवेदन है

और यहाँ तक कि गोचर भूमि के लिए भी। यह सराहनीय नहीं है कि सरकार ने एक न्यास/कंपनी के पक्ष में इस तरह के अनुचित पक्ष की पेशकश क्यों की। इस प्रकार, अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित लाभ थे - पक्षपात और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। [पैरा 8,19 और 8,21] [1023-ई-एच; 1024-ए, जी-एच]

दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य। , (2000) 7 एससीसी 296: [2000] 2 पूरक एस. सी. आर. 496; वी. चंद्रशेखरन और अन्न। बनाम। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य। , (2012) 12 एससीसी 133: [2012] 10 एससीआर 603; एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87:

82] [2023] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. 365; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ,

(1984) 3 एससीसी 161: [1984] 2 एस. सी. आर. 67; पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। टी. एन. राज्य, (2013) 1 एस. सी. सी. 585:

[2012] 9 एससीआर 579; देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2008) 1 एससीसी 728: [2007] 11 एससीआर 475; शहर

253 : [2009] 2 एस. सी. आर. 630 और सामान्य कारण, ए पंजीकृत सोसायटी बनाम भारत संघ और अन्य। (1999)

6 एससीसी 667: [1999] 3 एस. सी. आर. 1279 निर्दिष्ट है।

मामला

कानून संदर्भ

[2000] 2 पूरक। एससीआर 496

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.5

[2012] 10 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4.6

[1982] एससीआर 365

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.9

[1984] 2 एससीआर 67

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.9

[2012] 9 एससीआर 579

पै

रा 5.9

संदर्भित किया गया है

[2007] 11 एससीआर 475

पै

रा 5.24

संदर्भित किया गया है

[2009] 2 एससीआर 630

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5.24

[1999] 3 एससीआर 1279

पै

रा 5.26

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.1144

1146 2011 से।

उच्च न्यायालय के 16.11.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2009 के डब्ल्यू. पी. Nos.6863,2008 के 10325 और 12948 में कटक में उड़ीसा का।

के साथ

सिविल अपील सं। 1148-1150 , 1152-1154 और 2011 का 1161-1169।

एन. वेंकटरमन, संजय जैन, एएसजी, सी. आर्यमा सुंदरम,

प्रशांतो सेन, राकेश द्विवेदी, संजय पारिख, वरिष्ठ अधिवक्ता। , धनंजय मिश्रा, पी. एस. सुधीर, सुश्री अभिनी सौजन्या, नवनीत डोगरा, भरत सूद, सुश्री श्रुति जोस, आर्यन राय, मिलिंद कुमार, विशाल मेघवाल, आर्य त्रिपाठी, प्रशांत भूषण, प्रणव सचदेवा, चिनमाया मिश्रा, अजीत पुद्दुसरी, सातविक पारिख, वी. सी.

भारती, सुश्री प्रियंका दास, रजत नायर, एच. आर. राव, अरविंद कुमार शर्मा, रुपेश कुमार, सुश्री निशा बागची, अनुकल्प जैन, राघव शर्मा, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, उदय

खन्ना, ऋत्विक् पांडा, सुश्री निखार बेरी, सुश्री अंशु मलिक, अभिषेक

कुमार, राज कुमार मेहता, अमन झा, सुश्री बबीता यादव, रमन यादव, सुश्री शुभा यादव, गौरव प्रकाश शाह, ऋषि टूटू, सुश्री आकांक्षा, मनोज राजपूत, सुश्री रुचि कोहली, शिवाशीष मिश्रा, चंदन कुमार मंडल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2010 पर पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

रिट याचिका संख्या में पारित किया गया। 10325 2008, 2008 का 12948 और 2009 का 6863, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिकाओं को मंजूरी दी है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद "अधिनियम, 1894" के रूप में संदर्भित) की धारा 4 (1) और 6 के तहत अधिसूचनाओं और अपीलकर्ता-लाभार्थी कंपनी के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में पारित पुरस्कारों सहित विचाराधीन भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया है और निर्देश दिया है कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा संबंधित को बहाल किया जाएगा।

भूमि मालिक और भूमि मालिकों को अधिकार की बहाली पर, वे अपनी भूमि के संबंध में मुआवजे के रूप में या अन्यथा प्राप्त राशि को वापस कर देंगे। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि के नियम 5 के तहत लाभार्थी कंपनी के पक्ष में सरकारी भूमि के अनुदान को भी रद्द कर दिया है।

राज्य सरकार को उन भूमि को फिर से शुरू करने के निर्देश के साथ निपटान नियम जो लाभार्थी कंपनी को दिए गए थे पट्टा, अपीलार्थी-लाभार्थी कंपनी और अन्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, मूल भूमि मालिकों द्वारा दो रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिनके

भूमि का अधिग्रहण किया गया है और एक रिट याचिका दायर की गई है छोटे जमींदारों की ओर से जनहित याचिका, जो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सके और इलाके के लोगों की ओर से भी।

2.1 यह ध्यान देने योग्य है कि विवाद लगभग 6000 परिवारों की लगभग 6000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के संबंध में है। लगभग 30,000 लोगों को प्रभावित करता है।

3. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 कि 23.06.2006 पर, मोहित कुमार राणा, प्राचार्य, ए. टी. कर्नी लिमिटेड ने राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया।

यह कहते हुए कि एम/एस। वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, जनरल में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने के लिए उड़ीसा में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

विज्ञान और मानविकी आदि। आवेदन में आगे कहा गया कि समूह ने [2023] 8 एस. सी. आर. के माननीय मुख्यमंत्री को एक प्रस्तुति दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अप्रैल, 2006 के दौरान उड़ीसा। कि उड़ीसा के विभिन्न स्थलों का दौरा करने के बाद,

उनकी टीम ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आदर्श स्थान के रूप में पुरी-कोणार्क समुद्री ड्राइव पर पुरी के बाहरी इलाके में एक स्थान का चयन किया है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि उड़ीसा सरकार भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क समुद्री ड्राइव में पुरी जिले में नुआनाई के आसपास 15,000 एकड़ संलग्न भूमि उपलब्ध कराए। यह भी प्रार्थना की गई कि उड़ीसा सरकार को भी एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी की नियुक्ति करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का समन्वय करना चाहिए। समूह ने प्रार्थना की कि उन्हें सितंबर, 2006 तक अधिग्रहण किए जाने वाले पहले चरण के लिए 1500 एकड़ भूमि और दिसंबर, 2006 तक शेष भूमि की आवश्यकता है।

इसके बाद, उड़ीसा सरकार और वेदांत फाउंडेशन के बीच 19.07.2006 पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उड़ीसा सरकार ने लगभग 8000 एकड़ की सन्निहित भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की और फाउंडेशन द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सन्निहित भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया।

3.2 कि नाम में निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

और स्टर्लाइट फाउंडेशन की शैली ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत अपना नाम बदलकर वेदांता फाउंडेशन कर लिया और तदनुसार नाम परिवर्तन के परिणामस्वरूप जुलाई, 2004 में नया प्रमाण पत्र जारी किया गया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा फाउंडेशन को भूमि के आवंटन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए और वेदांत फाउंडेशन के उपाध्यक्ष को अनुमानित निवेश लागत का 20 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसे बाद में घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया और उच्च शिक्षा विभाग से परियोजना की प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए पुरी के कलेक्टर को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। विभाग और सरकार के समक्ष प्रस्ताव के साथ अनुमोदन प्रस्तुत करना।

3.3 राज्य के अनुसार, इस बीच, इन प्रश्नों पर विधि विभाग की राय मांगी गई थी:

- (क) क्या फाउंडेशन एक शिक्षा फाउंडेशन है? और
- (ख) क्या भूमि का अधिग्रहण जनता के लिए किया जाना आवश्यक है।

उद्देश्य?

3.4 इसके बाद विधि विभाग और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के बीच पत्राचार हुआ।

विधि विभाग ने पाया कि इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है अधिनियम, 1894 के तहत प्रस्तावित शैक्षिक योजना यदि सरकार का उपयुक्त विभाग इसे पूरा करने के लिए किसी योजना को प्रायोजित करता है।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

वैकल्पिक रूप से, किसी शैक्षणिक योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। एक सोसायटी द्वारा प्रायोजित लेकिन सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ।

अतः यह देखते हुए, विधि विभाग ने राय दी कि अधिनियम, 1894 के तहत, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है बशर्ते सरकारी प्रायोजक

सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ एक शैक्षिक योजना या एक पंजीकृत सोसायटी द्वारा निष्पादित करना। वैकल्पिक रूप से, इसने यह भी राय दी कि प्रशासनिक विभाग यह सत्यापित कर सकता है कि क्या उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 15 के तहत भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। उपरोक्त राय प्राप्त होने के बाद, प्रशासनिक विभाग का विचार था कि आईडीसीओ के माध्यम से जाने का दूसरा विकल्प व्यवहार्य नहीं था और उसने इस बात पर विचार करने का सुझाव दिया कि क्या उच्च शिक्षा विभाग परियोजना को सीधे प्रायोजित करेगा और इसका स्वामित्व लेगा और क्या यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा।

3.6 16.10.2006 पर आयोजित अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के निदेशक मंडल की एक बैठक में कंपनी की स्थिति को निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया 01.11.2006 पर वेदांत फाउंडेशन के नाम और संरचना में परिवर्तन। 24.11.2006 पर, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को पृष्ठ की कि कंपनी की स्थिति को एक निजी से एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया है। उसी दिन पुरी के कलेक्टर ने राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव को सार्वजनिक कंपनी का दर्जा बदलने के बारे में सूचित किया और

वेदांता की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भी

विश्वविद्यालय।

3.7 इसके बाद अधिनियम, 1894 की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचनाएं 6917.63 एकड़ के लिए 13.12.2006 से 21.08.2007 के बीच जारी की गईं।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त अधिसूचनाओं ने अन्य बातों के साथ संकेत दिया कि अधिग्रहण किया जा रहा था

अधिनियम, 1894 के अध्याय VII के संदर्भ में संचालित। इसके बाद अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत आपत्तियां मांगने के बाद अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत 5619.05 एकड़ के लिए एक घोषणा जारी की गई। अपीलार्थी के अनुसार, पुरस्कार घोषित होने के बाद, 3342 एकड़ अधिग्रहित भूमि और प्रायोजित 495 एकड़ सरकारी भूमि के संबंध में कब्जा दिया गया और 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया। 41.96 करोड़ रुपये भी वितरित किए गए।

3.8 चूंकि भूमि का एक विशाल हिस्सा गरीबों का था, छोटे किसानों और इस तरह से अधिग्रहित भूमि एक प्रतिष्ठित स्थान पर थी और हजारों

किसानों के परिवार भूमि के इतने बड़े हिस्से के अधिग्रहण से प्रभावित थे और वह भी एक निजी कंपनी के पक्ष में, जिसे बाद में दुर्भावनापूर्ण तरीके से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था, अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं।

3.9 विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, की खंड पीठ

उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका सहित रिट याचिकाओं को यह अभिनिर्धारित करते हुए अनुमति दी है कि:

और यह कि कथित रूप से भूमि पर कब्जा करना है धारा 4,5 ए, 6,9,10,11,12, (2), 23,24 के वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन, जिसे धारा 7 के तहत प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है।

अधिनियम, 1894। ;

फाउंडेशन ने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को दूषित कर दिया है। ;
((iii) कि बड़े पैमाने पर जनहित प्रभावित होता है और इसका उल्लंघन होता है।

कानून का शासन। ;

((iv) जनहित याचिका विचारणीय थी, जो उन छोटे भूमि धारकों की ओर से थी जिनके पास संपर्क करने के लिए कोई पोषण नहीं है।

यह न्यायालय मुकदमेबाजी लड़ने के लिए है। ;

(v) इसलिए, अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी तरह से उन व्यक्तियों के संबंध में है जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और यहां तक कि जिनके पास है

इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया गया है, इस कारण से रद्द किया जा सकता है

कि अधिनियम, 1894 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन हुआ है।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

3.10 इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 69 के संदर्भ में निम्नलिखित आदेश पारित किया है, जो इस प्रकार है:

" 69. नतीजतन, हम रिट याचिकाओं को अनुमति देते हैं, विवादित को रद्द करते हैं

संबंधित भूमि मालिकों से संपर्क किया जाए, भले ही उन्होंने अपनी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी हो या नहीं। भूमि मालिकों को अधिकार की बहाली पर, वे क्षतिपूर्ति के रूप में या अन्यथा अपनी भूमि के संबंध में उनके द्वारा प्राप्त राशि को वापस कर दें। हम सरकारी भूमि निपटान नियमों के नियम 5 के तहत लाभार्थी कंपनी के पक्ष में सरकारी भूमि के अनुदान को भी रद्द कर देते हैं, जिसमें राज्य सरकार को उन भूमि को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जाता है जो राज्य सरकार को दी गई थी।

लीज के माध्यम से लाभार्थी कंपनी। राज्य सरकार, भूमि मालिकों और लाभार्थी कंपनी सहित सभी संबंधित

उपरोक्त निर्देश को जल्द से जल्द लागू करेगा।

3.11 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश और अनुच्छेद 69 में आदेश का संचारी भाग

निर्णय वर्तमान अपीलों का विषय है।

4. संबंधित अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम और श्री राकेश द्विवेदी ने कहा,

दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने में भौतिक रूप से गलती की है और वह भी उन भूमि मालिकों के संबंध में जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई थी, अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती नहीं दी और/या उनमें से कई ने भी अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत कोई आपत्ति नहीं उठाई।

4.1 संबंधित की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलकर्ताओं ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने का अनुरोध किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया है। अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को दरकिनार करने वाला न्यायालय आवश्यक नहीं है:

यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचनाएं,

((i)

1894 13.12.2006 से 21.08.2007 के बीच जारी किया गया

6917.63 एकड़ के लिए; [2023] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ख)

अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणाएं जारी की गईं।

5619.05 एकड़ के लिए, इससे पहले अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं;

(iii) केवल 13 भूमि मालिकों, जो 78.89 एकड़ के मालिक थे, ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं; 25.61 एकड़ की सीमा तक 3 भूमि मालिकों के संबंध में आपत्तियां स्वीकार की गईं और 10 आपत्तियां खारिज कर दी गईं। 10 अस्वीकृतियों में से किसी ने भी किसी भी शिकायत के साथ किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था।

((iv) 3342 एकड़ अधिग्रहित भूमि के संबंध में कब्जा लाभार्थी के पक्ष में दिया गया।

495 एकड़ के संबंध में कब्जा भी दिया गया था।

(v)

सरकारी जमीन।

(vi) यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, कुल 3837 का कब्जा

एक एकड़ जमीन लाभार्थी को सौंप दी गई।

(vii) कि लाभार्थी पहले ही मुआवजे का भुगतान कर चुका है।

से रु. 41.96 करोड़।

(viii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुआवजे के अलावा, अनुग्रह राशि

रुपये की राशि। 25.13 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया गया।

(ix)

यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इस प्रकार, 3837 व्यक्तियों ने प्राप्त किया है

ऊपर के रूप में मुआवजा।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने पूरे अधिग्रहण को रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है

कार्यवाही।

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कुल 9 रिट याचिकाकर्ता थे

उच्च न्यायालय के समक्ष। उनमें से एक धारा 5 ए के तहत एक आक्षेपक था, हालाँकि, उसकी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से हटा दिया गया था। इसलिए, वह अब इस न्यायालय के समक्ष केवल एक पक्षकार हैं।

4.2. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं में से एक भूमि हारने वाला था, लेकिन धारा 5 ए के तहत आक्षेपकर्ता नहीं था। उसकी जमीन भी थी

धारा 6 के चरण में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही से हटा दिया गया।

4.2. 2 मूल रिट याचिकाकर्ताओं में से पाँच भूमि हारने वाले हैं, लेकिन धारा 5 ए के तहत विरोध करने वाले नहीं हैं।

4.2. 3 रिट याचिकाकर्ताओं में से दो जनहित याचिका याचिकाकर्ता हैं।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, आज तक, इस न्यायालय के समक्ष कुल 7 भूमि हारे हुए हैं, जिनके पास लगभग 11.52 एकड़ है,

हालाँकि, उनमें से किसी ने भी धारा 5 ए के तहत आपत्ति दर्ज नहीं की। लाभार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बार में कहा है कि अपीलकर्ता अब उनकी भूमि को अधिग्रहण कार्यवाही से बाहर करने के लिए तैयार है, भले ही उन्होंने धारा 5 ए आपत्ति दर्ज नहीं की हो।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में जहाँ तक उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिकाओं का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इससे पहले जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था।

2008 की याचिका (सी) संख्या 6981 जो जनहित याचिका रिट याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी। 4.5 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, कुछ को छोड़कर,

उक्त भूमि हारने वालों में से किसी ने भी धारा 5 ए के तहत कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि दिल्ली प्रशासन बनाम गुरदीप सिंह उबन और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है।, (2000) 7 एस. सी. सी. 296, सभी व्यक्तिगत प्रकृति की आपत्तियों को माफ माना जाता है।

4.6 वी. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए।

चंद्रशेखरन और अन्न। बनाम। प्रशासनिक अधिकारी और अन्य।, (2012) 12 एस. सी. सी. 133, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अधिग्रहण को एक भूमि हारने वाले द्वारा चुनौती दी जाती है, तो दूसरा इसका लाभ नहीं उठा सकता है यदि उसने अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत आपत्ति दर्ज नहीं की है।

4.7 यह आगे संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में

अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा के बाद और जांच करने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही को अंतिम रूप मिल गया है।

धारा 11 के तहत, पुरस्कार घोषित किए गए और अधिकांश भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान किया गया और यहां तक कि 3342 एकड़ तक का कब्जा भी लाभार्थी को सौंप दिया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, जब अधिग्रहण ने अंतिमता प्राप्त कर ली है, पुरस्कार दिए गए हैं, कब्जा कर लिया गया है और मुआवजा वितरित किया गया है तो पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को अलग करना वांछनीय नहीं है।

4.8 लाभार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि शुरू में भूमि को एक निजी कंपनी द्वारा अधिग्रहित करने की मांग की गई थी, लेकिन उसके बाद कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कंपनी को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था। वह हमें विभिन्न पत्राचारों और लाभार्थी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के आदेशों पर ले गए हैं।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.9 उन दस्तावेजों के आधार पर, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि

इसलिए उस समय जब धारा 4 अधिसूचना जारी की गई थी, लाभार्थी कंपनी को पहले ही एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था। इसलिए, लाभार्थी कंपनी के पक्ष में अधिग्रहण पूरी तरह से अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुरूप था। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि लाभार्थी न्यास/कंपनी के पक्ष में विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण एक विस्तृत परामर्श के बाद और शिक्षा आदि के क्षेत्र में न्यास/कंपनी के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाभार्थी कंपनी / न्यास चाहता है और/या एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता है।

उड़ीसा राज्य।

4.10 यह आगे लाभार्थी कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यदि विवादित निर्णय और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, अपीलार्थी की परियोजना को लागू करने में गंभीर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

4.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता-लाभार्थी ने 3837 एकड़ से अधिक भूमि के लिए एक दृष्टि योजना तैयार की है, जो वर्तमान में उनके अधिकार क्षेत्र में है।

अधिकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूरदर्शिता योजना 1,00,000 छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय प्रदान करती है और विश्वविद्यालय को चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पहले चरण में चिकित्सा, उदार कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महाविद्यालय

और डिजाइन संस्थान शुरू किया जाएगा।

4.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रख्यात शिक्षाविद पहले से ही हैं

परियोजना का सलाहकार/शैक्षणिक बोर्ड। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 41 समझौते में पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं कि भूमि का उपयोग विश्वविद्यालय के लिए किया जाएगा, और यदि भूमि के किसी भी हिस्से का उपयोग विश्वविद्यालय के उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, तो उक्त भाग

राज्य सरकार को लौटें।

4.13 यह आगे संबंधित अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अधिग्रहण के बाद भी

विचाराधीन भूमि, राज्य सरकार की नीति के अनुसार पुनर्वास उपाय किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

“ 1 .

राज्य सरकार की आर एंड आर नीति। एक आर एंड आर के तहत

230 विस्थापित परिवारों को समायोजित करने के लिए अधिग्रहित भूमि के भीतर
65.17 एकड़ की कॉलोनी अलग से स्थापित की गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आर एंड आर
कॉलोनी का स्थान विस्थापित परिवारों द्वारा स्वयं चुना गया है।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

परियोजना प्रभावित परिवार वरीयता के हकदार हैं।

2 .

विश्वविद्यालय में रोजगार के लिए।

अपीलार्थी ने सभी भूमि से एक स्नातक नियुक्त करने पर सहमति व्यक्त की है।

3 .

एक कर्मचारी के रूप में परिवारों को खोना।

4 .

अपीलार्थी भूमिहीन कृषि को शामिल करने के लिए सहमत हो गया है

अकुशल निर्माण श्रमिकों के रूप में श्रमिक। यदि वही प्रदान नहीं किया जाता है, तो एक निर्वाह भत्ता

रु. 1500 प्रत्येक परिवार को तारीख से प्रति माह भुगतान किया जाएगा।

2010 तक का अधिकार।

5 .

अपीलार्थी ने छात्रों के लिए खर्च वहन करने पर सहमति व्यक्त की है डी. ए. वी. स्कूल, पुरी में अध्ययन करने के लिए भूमि खोने वाले परिवारों से।

4.14 यह आगे उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

अपीलार्थियों की ओर से कि वर्तमान मामले में अधिनियम, 1894 की धारा VII और भूमि अधिग्रहण (कंपनियों) का अनुपालन है।

नियम, 1963 (इसके बाद "नियम, 1963" के रूप में संदर्भित)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, भाग VII का अनुपालन निम्नानुसार किया गया है:

भाग VII का अनुपालन इस प्रकार किया गया है:

" 1 .

(i)

धारा 39/40 राज्य द्वारा सहमति दी गई है।

सरकार।

((ii) धारा 40 (2)/नियम 4 के तहत पूछताछ की गई है। () एम (iii) फाउंडेशन द्वारा अनिवार्य रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं

धारा 41 के तहत।

((iv) धारा 44 बी लागू नहीं होती क्योंकि अपीलार्थी सार्वजनिक है।

कंपनी "।

4.15 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक नियम, 1963 हैं

संबंधित, अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि नियम 4 जांच केवल उस मामले में प्रासंगिक है जब भूमि की पहचान कंपनी द्वारा की जाती है न कि राज्य सरकार द्वारा और उसके बाद कंपनी द्वारा उक्त चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

वर्तमान मामले में, भूमि की पहचान न केवल राज्य सरकार द्वारा की गई थी (और इसलिए, अपीलार्थी लाभार्थी द्वारा नहीं), बल्कि नियम 4 के तहत परिकल्पना के अनुसार पर्याप्त रूप से जांच करने के बाद ऐसा किया गया था। अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में, अपीलकर्ता न्यास/लाभार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने निम्नलिखित तिथियों और घटनाओं पर विचार करने का अनुरोध किया है:

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

अप्रैल 2006-वेदांत रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री को एक प्रस्तुति दी गई। (नोट: इस प्रस्तुति में वेदांत द्वारा पहचानी गई कोई विशेष भूमि नहीं है) अप्रैल-जून, 2006-राज्य सरकार को इसकी जानकारी थी। कि

वेदांत समूह ने कुछ लोगों के लिए इसी तरह का प्रतिनिधित्व किया था।

अन्य राज्यों में भी। चूंकि इस प्रस्ताव ने राज्य के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत किया, इसलिए इसने अपने शीर्ष अधिकारियों, यानी मुख्य सचिव के नेतृत्व में उपयुक्त स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की और भूमि की पहचान करने की दिशा में एक विस्तृत जांच की। नियम 4 के तहत विचार

विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार। अंत में पुरी पर ध्यान केंद्रित किया।

बैठक, राज्य सरकार। अपीलार्थी के समक्ष पुरी में उसके द्वारा चिन्हित भूमि पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उक्त में भूमि की उपयुक्तता, उसके विस्तार, उसके तहत निवास आदि के बारे में विस्तार से विचार किया गया है। [ध्यान दें: यह नियम 4 (1) (i) और (iii) के अनुपालन को भी दर्शाता है]

23.06.2006 - राज्य द्वारा उपरोक्त प्रस्तुति के अनुसार, अपीलार्थी ने प्रस्तुति में प्रस्तावित स्थल का स्वतंत्र दौरा किया। इस आधार पर, ए. टी. केयर्नी (वेदांत द्वारा नियुक्त एक सलाहकार) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि वेदांत पुरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने में रुचि रखता है।

26.06.2006- राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, अतिरिक्त सचिव। जिला मजिस्ट्रेट, पुरी और तहसीलदार, पुरी ने परियोजना क्षेत्र का दौरा किया।

उपरोक्त अभ्यास के दौरान:

ए) एडिशनल। पुरी के जिला मजिस्ट्रेट और कार्य सचिव ने भी स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया। [ध्यान दें: यह नियम 4 (1) (i)] GARWAL FOUNDATION ETC के अनुपालन को भी दर्शाता है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

गाँव में अनौपचारिक समूह बैठकों की संख्या

ख)

कलेक्टर और अन्य राज्य सरकारों के बीच। अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने से पहले अधिकारी। यह भूमि अधिग्रहण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए किया गया था। भूमि की उपयुक्तता सहित, और भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य के बारे में ग्रामीणों का मूल्यांकन करना; [नोट: यह नियम 4 (1) (i) के अनुपालन को भी दर्शाता है और

(iii)]

पता लगाने के उद्देश्य से दौरे भी किए गए थे

(ग)

कि विभिन्न वैकल्पिक स्थानों में से न्यूनतम विस्थापन हो रहा था यह देखने के लिए भी निर्धारण किया गया था कि अपीलार्थी

(घ)

जमी हुई भूमि का उपयोग करने में सक्षम है, तेजी से; विभिन्न समीक्षाओं में, भूमि की आवश्यकता को घटाकर 6000 एकड़ कर दिया गया था; [नोट: यह नियम 4 (1) (iv) और (v) के अनुपालन को भी दर्शाता है।

यह पता लगाने के लिए भी अभ्यास किया गया कि

ई)

भूमि वर्षा से पोषित होती है; सिंचित नहीं होती; बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली नहीं होती है।

कृषि भूमि; निम्न, अनुत्पादक और परती भूमि। [ध्यान दें: यह नियम के अनुपालन को भी दर्शाता है।

4 (1) (vi)]

परियोजना क्षेत्र के अधिकांश भूमि विस्थापित थे

च)

उचित मूल्य के भुगतान के लिए बातचीत करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा बैठकों में संपर्क किया गया। [ध्यान दें: यह नियम 4 (1) (ii) के अनुपालन को भी दर्शाता है]

19.07.2006 - राज्य को होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों के बारे में संतुष्ट होने के बाद, प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। [ध्यान दें: के साथ अनुपालन

09.08.2006- राज्य सरकार। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के समन्वय के लिए आर एंड आर के लिए एक विशेष एल. ए. ओ. और विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। 29.11.2006 - राज्य सरकार ने संतुष्ट होने पर इस परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xi) 7 कोर कमेटी की बैठकों के कार्यवृत्त

02.09.2006 और 07.02.2008 भी पर्याप्त रिकॉर्ड करता है

नियम 4 का अनुपालन।

4.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक अनुपालन है

नियम 3 (1) और 3 (2)। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 4 भी

बाद में झूठ बोला।

4.17 राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील

एनमेंट ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, वहाँ है

अधिनियम, 1894 की धारा 4,5 ए, 6,9,11 और 12 का अनुपालन। अनुपालन के समर्थन में निम्नलिखित तिथियों और घटनाओं पर विचार करना है।

अधिनियम, 1894 के तहत प्रावधानों के साथ राज्य सरकार, जो

इसके अंतर्गत:

धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है

" 1 .

आधिकारिक राजपत्र, और दो दैनिक समाचार पत्रों में

उस इलाके और कलेक्टर ने अधिसूचना के सार के बारे में सार्वजनिक सूचना का उपयोग किया है एस. 4 (1) की पिटाई के माध्यम से

Sec.4 (1) के तहत इलाके में सुविधाजनक स्थानों पर ढोल

2 .

अधिनियम में कारणदर्शक नोटिस देने का कोई प्रावधान नहीं है।

यू/एस द्वारा आपत्तियाँ आमंत्रित करने के लिए इच्छुक व्यक्ति। 5 ए. एल. ए. अधिनियम, 1894 में राज्य संशोधन के कारण कर्नाटक में भी यही आवश्यकता है।

उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के माध्यम से लागू किया गया है, भले ही उड़ीसा में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।

3 .

13 एक क्षेत्र के लिए 6 गाँवों से प्राप्त आपत्ति याचिकाएँ

एसी 78.89 को मापना। द स्प्ल. भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने

यू/एस 5-ए सुनने के लिए विरोध करने वालों को नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ताओं को सुना। आपत्ति याचिकाओं को सरकार को भेज दिया है। जिला कलेक्टर के माध्यम से राजस्व विभाग में अपनी रिपोर्ट और कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ। वास्तव में, 13 आपत्तियों में से 3 की अनुमति दी गई थी (25.61 एकड़)। 10 अस्वीकृतियों में से किसी ने भी किसी के साथ किसी भी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया।

शिकायतें।

राज्य सरकार। घोषणा की सार्वजनिक सूचना दी है

4 .

धारा 6 (2)।

कलेक्टर ने यू/एस नोटिस जारी किए हैं। 9 (1) गाँव में

5 .

और इच्छुक व्यक्तियों को यू/एस। 9 (3) उन्हें मुआवजे का दावा दायर करने के लिए बुलाना, जैसा कि एल. ए. रिकॉर्ड में स्पष्ट है।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

6 .

उनके संबंधित हितों की जांच करने के बाद, दावे

क्षेत्र के लिए मुआवजे और आपत्तियों के लिए, जो इच्छुक व्यक्तियों ने नोटिस यू/एस के अनुसार कहा है। 9 , कलेक्टर यू/एस। 11 भूमि के वास्तविक क्षेत्र पर अधिनिर्णय पारित किया है, मुआवजे की अनुमति और मुआवजे का विभाजन।

7 .

एल. ए. अधिनियम, 1894 के तहत मुआवजे के अलावा,

रुपये की अनुग्रह राशि। 1 प्रति एकड़ एक लाख रुपये के न्यूनतम मुआवजे के अधीन। 2 आर. पी. डी. ए. सी. (राज्य आर. एंड आर. नीति के अनुसार गठित) द्वारा अनुमोदित एक लाख एकड़ भूमि का भुगतान किया जाना था।

यह विभिन्न अन्य लाभों के अलावा है

प्रदान किए गए, जिन्हें (I) में गिना गया है। उपरोक्त पृष्ठ 3 पर इस टिप्पणी का बी।

8 .

कलेक्टर ने ऐसे इच्छुक लोगों को अपने पुरस्कार का नोटिस दिया है।

व्यक्ति यू/एस। 12 (2) एल. ए. अधिनियम 1894, जैसा कि एल. ए. में स्पष्ट है

अभिलेख "।

4.18 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में परियोजना किसी भी मामले में नहीं आती है।

निषिद्ध क्षेत्र। यह तटीय नियामक क्षेत्र से परे है। प्रस्तावित वेदांत विश्वविद्यालय से समुद्र की दूरी 2000 मीटर से अधिक है। बालुखंड वन्यजीव अभयारण्य प्रस्तावित स्थल से एक राजमार्ग/पुरी-कोणार्क मरीन ड्राइव द्वारा अलग किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभयारण्य समुद्र की ओर है, जबकि प्रस्तावित स्थल भूमि की ओर है।

4.19 यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई निजी संस्थान हैं

और संगठन जो प्रस्तावित विश्वविद्यालय के रूप में राजमार्ग के एक ही तरफ हैं, साथ ही एक बड़ी आबादी वाले पूरे बेलदाला गांव के साथ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल से बहने वाली नुआनई एक नदी नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें दो मानव निर्मित चैनल (गबकुंड कट और सियार कट) शामिल हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन चैनलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इन दोनों चैनलों का स्वामित्व अभी भी उड़ीसा सरकार के

जल संसाधन विभाग के पास है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में, पर्यावरण मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सभी पर्यावरणीय आवश्यकताओं की जांच की जाएगी और उन पर गौर किया जाएगा।

4.20 संबंधित की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी हमें उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और उनकी प्रतिक्रिया तक ले गए हैं, जिन्हें मोटे तौर पर ऊपर संदर्भित किया गया है।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.21 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान की अनुमति दी जाए

अपीलें करें। 5. संबंधित पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया है।

उत्तरदाता-मूल रिट याचिकाकर्ता।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में लगभग 6000 परिवारों की लगभग 6000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शामिल है, और इस प्रकार, लगभग 30,000 लोगों का विस्थापन शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा सरकार ने इस पर भारी उदारता दिखाई है

अपीलार्थी कंपनी ने स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से कार्य करके और अपीलार्थी कंपनी के पक्ष में संबंधित भूमि के अधिग्रहण का पूर्व-निर्धारण करके अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 के सभी अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा सरकार की उक्त अवैध कार्रवाई जनहित के समर्थन के लिए पर्याप्त कारण को जन्म देती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 6000 एकड़ भूमि के इतने बड़े हिस्से को आवंटित करने में राज्य की कार्रवाई और वह भी प्रमुख स्थान पर, जो पक्षपात के एक स्पष्ट मामले के अलावा और कुछ नहीं था और

मनमानी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से दरकिनार कर दिया गया है।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सहित

धारा 4 (1) और 6 के तहत अधिसूचनाएं और भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही में पारित पुरस्कार

लाभार्थी कंपनी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश द्वारा सही ढंग से रद्द कर दिया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5.3 यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों/भूमि हारने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भूमि की पहचान अपीलकर्ता कंपनी द्वारा की गई थी, न कि सरकार द्वारा, जैसा कि तिथियों और घटनाओं के कालक्रम और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के नोट शीट से स्पष्ट होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोट शीट स्पष्ट रूप से दर्शाती है, अन्य बातों के साथ, कि अपीलकर्ता कंपनी ने उड़ीसा सरकार से विशेष रूप से उपलब्ध कराने के लिए कहा था

इसके लिए भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क में नुआनाई, पुरी जिले के आसपास 15,000 एकड़ संलग्न भूमि 15.06.2006 द्वारा।

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 19.07.2006 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रासंगिक खंड भी यह दर्शाते हैं कि भूमि की पहचान कंपनी द्वारा की गई थी न कि सरकार द्वारा।

यह ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. है। ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

प्रस्तुत किया कि दिनांक 19.07.2006 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, यह वेदांता फाउंडेशन ही था जिसने उड़ीसा में पुरी के पास एक स्व-नियंत्रित बस्ती के साथ विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, जिसकी अनुमानित लागत रु। 15,000 करोड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त समझौता ज्ञापन में भी प्रस्तावित स्थान का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा सरकार ने अभी-अभी लगभग 8000 एकड़ की सन्निहित भूमि की उपलब्धता की पुष्टि की है। [समझौता ज्ञापन का खंड 5]

5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 41 समझौते को भी निष्पादित किया गया है।

उड़ीसा सरकार और अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बीच यह भी पता चलता है कि भूमि की पहचान कंपनी द्वारा की गई थी न कि कंपनी द्वारा। उक्त समझौते के अनुसार सरकार का कहना है कि कंपनी का इरादा पुरी के पास वेदांत विश्वविद्यालय स्थापित करने का था और उसने अनुसूची में वर्णित भूमि के अधिग्रहण के लिए उड़ीसा सरकार को आवेदन किया था

5.6 मूल रिट याचिकाकर्ताओं-मूल भूमि मालिकों/भूमि हारने वालों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा सरकार, पूरी तरह से अच्छी तरह से जानने के बावजूद कि वेदांत फाउंडेशन का शिक्षा के क्षेत्र में कोई पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, ने दिनांक 19.07.2006 के समझौता ज्ञापन में कई खंड शामिल किए, जो अनुचित उदारता प्रदान करते हैं। वेदांत को प्रशासन, प्रवेश, शुल्क संरचना, पाठ्यक्रम और संकाय चयन के संबंध में वेदांत विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को पूर्ण स्वायत्तता; प्रस्तावित विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के किसी भी आरक्षण कानून से पूर्ण प्रतिरक्षा, यू. जी. सी., ए. आई. सी. टी. ई. आदि से नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में सभी सहायता। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार भी सरकार भुवनेश्वर शहर से प्रस्तावित स्थल तक 4 लेन की सड़क प्रदान करने पर सहमत हो गई है और उड़ीसा सरकार वेदांत के साथ परामर्श के बाद ही विश्वविद्यालय की सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में भूमि उपयोग/क्षेत्र निर्धारण योजना बनाएगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने सभी राज्य शुल्कों/करों/शुल्कों को छूट देने का भी वादा किया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से अनुसंधान और विकास उपकरण, शैक्षिक सहायता, प्रयोगशाला उपकरण और उपकरण और निर्माण सामग्री पर वैट, कार्य अनुबंध कर, स्टाम्प शुल्क और प्रवेश कर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने एस. पी. सी. वी. से एन. ओ. सी. और केंद्र सरकार से सभी मंजूरी प्राप्त करने में फाउंडेशन की सहायता करने का भी वादा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने परियोजना के लिए तेजी से ई. आई. ए. और ई. एम. पी. की व्यवस्था करने में फाउंडेशन की सहायता करने का भी वादा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार ने [2023] 8 एस. सी. आर. की असाधारण भारी राशि प्रदान करने का भी वादा किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली और पानी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकार की उपरोक्त भूमिका एक निजी न्यास/कंपनी के पक्ष में स्पष्ट पक्षपात दिखाती है।

- वेदांत फाउंडेशन।

5.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा सरकार ने अपीलकर्ता कंपनी की मांग की वास्तविकता के बारे में अपने दिमाग को लागू नहीं किया

10.000 परिसर के निर्माण के लिए एकड़। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह ध्यान देने योग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक-स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का लगभग 8,100 एकड़ का कम सन्निहित क्षेत्र है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उड़ीसा सरकार ने उपलब्धता की पुष्टि की

8000 और अपीलार्थी कंपनी द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सन्निहित भूमि प्रदान करने का वादा किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रासंगिक समय में, फाउंडेशन एक परिवार के 3 सदस्यों के साथ एक निजी कंपनी थी और रुपये की गारंटी द्वारा सीमित थी। 5,000 / - , और शिक्षा में कोई पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सेक्टर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वेदांत फाउंडेशन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सरकार ने पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया और इस बात पर विचार नहीं किया कि क्यों वेदांत समूह को विभिन्न सरकारों/अधिकारियों/अदालतों/न्यायाधिकरणों और एजेंसियों द्वारा खनन कानूनों, पर्यावरण कानूनों, प्रदूषण पैदा करने और उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक में अपनी खनन परियोजनाओं में मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर उल्लंघन के लिए बार-बार दोषी ठहराया गया है।

5.8 विवादित फैसले के पैरा 63 से 67 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर हमें ले जाते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह ठहराने के लिए ठोस कारण और निष्कर्ष दिए हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से मनमाने तरीके से की गई थी और इसने जनहित को पराजित किया था। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि इसलिए, उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर उचित रूप से विचार किया है जिसमें कहा गया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही की शुरुआत वेदांता फाउंडेशन द्वारा तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके की गई मांग पर लाभार्थी कंपनी का पक्ष लिया गया, जिसने पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दूषित कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने सही अवलोकन किया है और कहा है कि बड़े पैमाने पर जनहित प्रभावित होता है और कानून के शासन का उल्लंघन होता है।

5.9 जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन है कि लगभग 6000 लोगों में से केवल 7 लोगों ने धारा 5 ए की आपत्तियाँ दायर की हैं,

जो लोग अपनी भूमि खो रहे थे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तथ्य यह है कि केवल 7 लोगों ने अपनी आपत्तियाँ दायर कीं, यह दर्शाता है कि भूमि मालिक या तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से अनजान थे और/या बहुत कमजोर, गरीब और वंचित थे और वे एन. ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. ए. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. दाखिल करने की स्थिति में भी नहीं थे। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्या [एम. आर. शाह, जे.]

कलेक्टर के साथ आपत्तियाँ। एस. पी. गुप्ता बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। भारत संघ, 1981 पूरक एस. सी. सी. 87;

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. सी. 161 और पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम टी. एन. राज्या, (2013) 1 एस. सी. सी. 585, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने जनहित याचिकाओं पर उचित रूप से विचार किया है और पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को सही ढंग से रद्द कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने 6000 एकड़ की सीमा तक भूमि के इतने बड़े हिस्से के अधिग्रहण द्वारा जनहित याचिकाओं पर उचित रूप से विचार किया है और अनुमति दी है, जिससे 30,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जो बहुत कमजोर, गरीब और वंचित थे, जो कानूनी निवारण के लिए अदालत का रुख नहीं कर सकते थे।

5.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जनहित याचिकाओं के अलावा, भूमि हारने वालों ने भी अधिग्रहण को चुनौती दी थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को सही ढंग से रद्द कर दिया है। यह पाया गया है कि विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों ने बार-बार पूरे अधिग्रहण को रद्द कर दिया है जहां अवैधता मामले की जड़ तक जाती है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखे जाने और अभिनिर्धारित किए जाने के बावजूद, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही थी

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में मनमानेपन और अधिनियम, 1894 और वैधानिक नियमों के उल्लंघन से पीड़ित।

5.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी एक निजी कंपनी है, और

सार्वजनिक कंपनी नहीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी दावा करता है कि वह धारा 25 के तहत पंजीकृत एक निजी कंपनी थी

उक्त लाइसेंस के अनुसार, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किसी भी बदलाव को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें, प्रस्ताव, दिनांक 23.11.2006, अपीलार्थी द्वारा इसे एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए संघ के लेखों में परिवर्तन करना और सदस्यों को 7 तक बढ़ाने को केंद्र द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी

सरकार ने धारा 25 के तहत उसे जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार और इसलिए, कंपनी कभी भी सार्वजनिक कंपनी नहीं बनी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

कंपनी पंजीयक की ओर से उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे से भी उपरोक्त बात स्पष्ट है। वह हमें प्रासंगिक पैराग्राफ अर्थात् पैराग्राफ संख्या पर ले गए हैं। 9, 10 और द्वारा दायर हलफनामे के 12

कंपनी पंजीयक दिनांक 15.10.2008 ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय से दिनांकित 22.11.2006 पत्र पर वेदांता की निर्भरता कंपनी के सार्वजनिक कंपनी बनने का कोई सबूत नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह केवल [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेदांता का कहना है कि "कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (8) के तहत अनुमति के लिए वेदांता के अनुरोध पर एतद्वारा कंपनी की स्थिति के रूपांतरण पर विचार किया जाता है।

निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23,31,189 (2) और 192 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन था, जिनका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जाता है।

5.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यही कारण है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को सरकार की कोर समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, जिसके बिना कोई भी कंपनी की प्रकृति को समझ नहीं सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी की प्रकृति, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, शेयरों के धारण की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि सदस्य शेयरों को संयुक्त रूप से धारण करें, फिर अधिनियम, 1956 की धारा 3 (सी) के प्रावधान के अनुसार, उन्हें केवल एक सदस्य के रूप में माना जाएगा। इसके अलावा, धारा 25 पंजीकृत कंपनी के लिए भी इसके सदस्यों की जवाबदेही के बारे में अधिनियम, 1956 की धारा 12 (5) का पता नहीं लगाया जा सका। तदनुसार,

सदस्यों, जैसा कि बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त से देखा जा सकता है, सभी अग्रवाल कंपनी को संयुक्त रूप से रखते हैं, और इसलिए, यह केवल एक निजी कंपनी हो सकती है। कंपनी।

5.13 हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के दिनांकित 10.02.2011 पत्र में, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उनके पास कोई शेयर नहीं है और वह अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत गारंटी पर पंजीकृत कंपनी है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई शेयर नहीं होते हैं, तो होल्लिंग का पैटर्न

शेयरों का संयुक्त रूप से या अलग-अलग निर्धारण नहीं किया जा सकता है और इसलिए कंपनी केवल एक निजी कंपनी हो सकती है।

5.14 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 31.07.2007 पर निष्पादित समझौते में भी, अपीलकर्ता कंपनी खुद को केवल एक कंपनी के रूप में उल्लेख करती है, लेकिन खुद को एक सार्वजनिक कंपनी नहीं बताती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी भी अधिनियम, 1956 की धारा 44 के तहत अनिवार्य अनुसूची IV में विवरण-पत्र या बयान दाखिल करने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूची IV में प्रत्येक निदेशक के हित का खुलासा किया जाता है

5.15 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक सार्वजनिक कंपनी, अधिनियम, 1894 के संदर्भ में, संघ के अनुच्छेदों में प्रावधान की आवश्यकता होगी जो किसी भी निजी कंपनी के आधार को हटाने के लिए शेयर खरीदने के लिए सार्वजनिक।

यह ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. है। ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम, 1894 की धारा 44 बी के दायरे और उद्देश्य पर विचार करना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा 40 और उसके लिए बनाए गए नियमों के तहत एक जांच पर विचार किया जाता है। 5.16 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 41 समझौते के खंड 13 में भी दो तिहाई से अधिक, यानी 66.66% का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया गया है।

मुआवजे का निर्धारण किया गया जो धारा 17 (3 ए) (3) का घोर उल्लंघन है जो मुआवजे का 80 प्रतिशत भुगतान करने के लिए अनिवार्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी, अधिनियम में प्रवेश करने/कब्जा करने से पहले 80 प्रतिशत का भुगतान करना अनिवार्य है, लेकिन निजी कंपनी के लिए, उपरोक्त समझौते में 66.67% से अधिक का भुगतान नहीं करना अनिवार्य है जो कि अस्वीकार्य है।

5.17 यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 41 समझौते को भी झूठे आधार पर निष्पादित किया गया था क्योंकि धारा 40 के तहत ऐसी कोई जांच अनिवार्य नहीं थी।

अधिनियम, 1894 आर/डब्ल्यू नियम, 1963 का संचालन किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए धारा 41 समझौता अनुचित देने के लिए शक्ति का एक धोखाधड़ीपूर्ण प्रयोग था

अपीलार्थी के पक्ष में।

5.18 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, स्वीकार्य रूप से, 19.07.2006 पर अपीलार्थी के साथ समझौता ज्ञापन के निष्पादन के समय, अपीलार्थी

यह एक निजी कंपनी थी और इसलिए, प्रस्ताव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, सरकार ने अनुचित रुचि दिखाई और पूरी सरकारी मशीनरी ने जल्दबाजी में काम किया और इसका उपयोग करके भूमि का अधिग्रहण किया।

आपातकालीन प्रावधान, अर्थात् अधिनियम की धारा 17। यह प्रस्तुत किया जाता है कि

आई. डी. 1 पर भी कंपनी सार्वजनिक कंपनी नहीं थी। इसलिए, भूमि अधिग्रहण का आधार बनने वाली एक निजी कंपनी, अपीलार्थी के साथ समझौता ज्ञापन/समझौता करना वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। धारा 40 (1) (ए) और 40 (1) (बी) और 44-बी के तहत बार और इसलिए, शुरुआत से ही शून्य है।

5.19 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी की निर्भरता

कलेक्टर का पत्र, दिनांक 25.07.2008, जो धारा 6 के बाद था अधिसूचना असमर्थनीय है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलेक्टर की जांच और रिपोर्ट को धारा 6 अधिसूचना से पहले आगे बढ़ना था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नियम, 1963, [2023] 8 एस. सी. आर. के तहत कोई जांच भी नहीं की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसे विशेष द्वारा प्रतिक्रिया से स्थापित और साबित किया गया है

आर. टी. आई. प्रश्न दिनांक 27.05.2008 के लिए भूमि अधिग्रहण अधिकारी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आर. टी. आई. प्रश्न के उत्तर में, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने जवाब दिया है कि; "भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963 के तहत ऐसी कोई जांच नहीं थी"।

5.20 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में भी, नहीं

5.21 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च शिक्षा विभाग, सरकार द्वारा गठित 'कोर कमेटी' उड़ीसा दिनांकित अधिसूचना 17.08.2007 के माध्यम से, स्पष्ट रूप से के लिए स्थापित किया गया था

सरकारी भूमि के पट्टे और निजी भूमि के अधिग्रहण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना, नीति के अनुसार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना, यू. जी. सी. ए. आई. सी. टी. ई., एम. सी. आई., बी. सी. आई. आदि के रूप में प्रासंगिक वैधानिक निकायों से मान्यता प्राप्त करने में तेजी लाना, विश्वविद्यालय के लिए एक अधिनियम बनाना, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में सुविधा प्रदान करना और इसके प्रावधान में तेजी लाना।

विश्वविद्यालय आदि के लिए आवश्यक सड़क, पानी, बिजली और टेलीफोन संपर्क। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त कोर समिति की स्थापना का दायरा, संरचना और उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के दायरे, संरचना और उद्देश्य से पूरी तरह से अलग है।

नियम, 1963 के नियम 3 के तहत परिकल्पित समिति। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए एक कंपनी से प्रस्ताव की व्यवहार्यता और वांछनीयता का मूल्यांकन करने में सरकार की सहायता के लिए भूमि अधिग्रहण समिति की स्थापना की आवश्यकता होती है, लेकिन भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कोर समिति का गठन किया गया था

उड़ीसा सरकार ने पहले ही निर्धारित कर लिया है कि वैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट उल्लंघन में अधिग्रहण की व्यवहार्यता और वांछनीयता।

5.22 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी का तर्क है कि जाँच

नियम, 1963 के नियम 4 के तहत वर्तमान मामले में आवश्यक/प्रासंगिक नहीं था क्योंकि भूमि की पहचान सरकार द्वारा की गई थी न कि सरकार द्वारा।

कंपनी, पानी नहीं रखती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा स्थापना के समय से ही भूमि की स्पष्ट रूप से पहचान की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी, क्या भूमि है

कंपनी या सरकार द्वारा चिन्हित, वैधानिक नियम 4 को बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया जा सकता है और कलेक्टर सभी ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. ए. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. की जांच करने के लिए बाध्य है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

नियम, 1963 के नियम 4 में उल्लिखित बातें, अन्यथा पूरा उद्देश्य नियम, 1963 और अधिनियम, 1894 के भाग VII को निरस्त कर दिया जाएगा। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिकांश गांवों के लिए घोषणाएं भी अधिनियम की धारा 41 के तहत समझौते के निष्पादन से पहले की गई थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह नियम, 1963 के नियम 4 (4) (ii) का पूर्ण उल्लंघन और उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि उपयुक्त द्वारा कोई घोषणा नहीं की जाएगी।

अधिनियम की धारा 6 के तहत सरकार जब तक कि इसके तहत समझौता न हो

5.23 विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, शुरू से ही और हस्ताक्षर करने के समय से समझौता ज्ञापन, उड़ीसा सरकार ने अपना मन बना लिया था कि भूमि वेदांत को उपलब्ध होगी, भले ही अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाना बाकी था, जिसके कारण अधिग्रहण की संभावित विफलता हो सकती थी क्योंकि इसमें प्रदान की गई पूछताछ का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण को बाहर करना है यदि कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है।

5.24 विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण ने देविंदर सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

पंजाब राज्य, (2008) 1 एस. सी. सी. 728 और सिटी मोंटेसरी स्कूल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 14 एस. सी. सी. 253 उनके समर्पण के समर्थन में कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 के भाग VII द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, सख्त अनुपालन की आवश्यकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1894 के भाग VII और प्रासंगिक नियम, 1963 की सभी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है।

5.25 विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, जांच और आपत्ति के तहत

अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए का ठीक से पालन और/या पालन नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कलेक्टर के लिए प्रभावित लोगों की आपत्तियों को ठीक से सुनना बिल्कुल महत्वपूर्ण था।

प्रस्तावित [2023] 8 एस. सी. आर. की वांछनीयता के संबंध में धारा 5 ए के अनुसार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परियोजना, प्राप्त आपत्तियों की संख्या के बावजूद और होनी चाहिए उसके अनुसार एक रिपोर्ट बनाई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, कलेक्टर द्वारा उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

5.26 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी विवादित भूमि अधिग्रहण पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लाभार्थी कंपनी के पक्ष में विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से गलत है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित भूमि के पास के क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य और दो नदियों के रूप में घोषित किया गया है। वन विभाग द्वारा जारी उपग्रह मानचित्र के अनुसार अधिग्रहित भूमि में "नुआनाई" और "नाला" बह रहे हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नदियों का नियंत्रण उक्त निजी कंपनी के अधीन होगा यदि

अधिग्रहण की कार्यवाही को कानून में वैध माना जाता है जिससे इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य कारण के मामले में, एक पंजीकृत सोसायटी, (1999) 6 एस. सी. सी.

667 , इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वायु, जल, वन, झील, नदी और वन्यजीव जैसे प्राकृतिक संसाधन सार्वजनिक संपत्ति हैं जो सरकार को उनके सुरक्षित और उचित उपयोग और उचित सुरक्षा के लिए सौंपी गई हैं और यह सिद्धांत सरकार को निजी स्वामित्व या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग की अनुमति देने के बजाय आम जनता के आनंद के लिए संसाधनों की रक्षा करने का आदेश देता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वेदांता कंपनी के लिए की गई मांग के आधार पर गोचर भूमि सहित राज्य सरकार से संबंधित भूमि के विशाल हिस्से को भी आरक्षित कर दिया गया था और उस उद्देश्य से विभाजित कर दिया गया था जिसके लिए इसे आरक्षित किया गया था और पट्टा के माध्यम से लाभार्थी कंपनी के पक्ष में अनुदान के लिए उपलब्ध कराया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पट्टा देने के लिए उचित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है।

5.27 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बाद में एक निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में रूपांतरण भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई/अधिनियम था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता कंपनी को निजी से कथित रूप से सार्वजनिक कंपनी में बदलने के लिए पूरी कवायद जल्दबाजी में की गई थी, जब उसके लिए पहले से ही भूमि अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था और अधिग्रहण कार्यवाही के दौरान कानून विभाग ने देखा कि भूमि का अधिग्रहण केवल एक सार्वजनिक कंपनी के लिए किया जा सकता है और इस तरह जल्दबाजी में अपीलकर्ता कंपनी को दिए गए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए संघ के लेख और संघ के ज्ञापन को बदल दिया गया था और

पहले संबंधित प्राधिकारी को परिवर्तन के बारे में सूचित किए बिना, जो दर्शाता है कि यह अभ्यास अधिनियम, 1894 के भाग VII के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विफल करने के लिए किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान में स्वामित्व एन. आई. एल. अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्या। [एम. आर. शाह, जे.]

भूमि अभी भी भूस्वामियों के पास है और जिनमें से अधिकांश कृषक हैं और उनकी अधिग्रहित कृषि भूमि ही आजीविका का एकमात्र स्रोत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, लगभग 6000 परिवारों और 30,000 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है, अगर जमीन छीन ली जाती है, तो इससे उन्हें बहुत कठिनाई होगी जिसकी भरपाई कभी भी आर्थिक रूप से नहीं की जा सकती है।

5.28 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है

अपीलें करें।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनकर

और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को देखने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करते हुए, उच्च न्यायालय ने वास्तव में 15 की पहचान की थी

मुद्दे, जो इस प्रकार हैं:

मुद्दे

मुद्दा संख्या 1

क्या अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, लाभार्थी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1) (IV) के तहत परिभाषा के संदर्भ में एक सार्वजनिक कंपनी है और क्या निजी गारंटी सीमित कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है?

मुद्दा संख्या 2

(कंपनी) नियम, 1963?

अंक

संख्या 4

(क) क्या कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 5-क के तहत विचार के अनुसार एक जांच करने की आवश्यकता थी, भले ही भूमि मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों के पक्ष में भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करने वाली प्रारंभिक अधिसूचना के साथ कारण बताएँ नोटिस पर आपत्तियां दर्ज न की गई हों।

एक लाभार्थी कंपनी का?

और

(ख) क्या कलेक्टर को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। नियम-4 के खंड (1) के तहत निर्दिष्ट कुछ मामलों के संबंध में क्योंकि यह एल. ए. अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत आगे की कार्रवाई के लिए अनिवार्य है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिग्रहण के गंभीर नागरिक परिणाम होंगे।

जमीन के मालिक?

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंक संख्या 5

(क) क्या विचाराधीन भूमि के मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों ने छूट दे दी है।

या प्रारंभिक के लिए आपत्तियाँ दायर नहीं करने के लिए अपने अधिकारों को स्वीकार किया अधिसूचनाएँ?

और

(ख) क्या इन रिट याचिकाओं में कोई देरी और अड़चनें हैं और इस कारण से वे राहत के हकदार नहीं हैं जैसा कि इन रिट याचिकाओं में अनुरोध किया गया है?

अंक संख्या 6 और 7

6. क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोर समिति। एल. ए. अधिनियम, 1894 की धारा 40, उप धारा (2) के तहत प्रावधान का अनुपालन करता है और इसने एक जांच की है और राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर विचार करने और उनके अनुपालन के लिए भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963 के नियम 3 और 4 को समाप्त किया जा सकता है।

एल. ए. अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा?

और

7. क्या राज्य सरकार ने नियम, 1963 के नियम 3 (2) और 4 का पालन किया है और कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और उसे इस उद्देश्य के लिए गठित समिति को भेज दिया गया है और क्या उसने नियम घोषित करने से पहले समिति से परामर्श किया है।

धारा 6 अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित और प्रकाशित भूमि?

अंक संख्या 8 और 9

8 . क्या लाभार्थी कंपनी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 41 के तहत राज्य सरकार के साथ अधिनियम की उक्त धारा की उप धारा (1), (2) और (3) के तहत दिए गए वचन पत्र को लागू किया है और यह अधिनियम में प्रकाशित किया गया है।

इसकी धारा 42 के तहत आवश्यक आधिकारिक राजपत्र?

और

9. क्या लाभार्थी कंपनी द्वारा निष्पादित दिनांक 19/07/2006 के समझौता ज्ञापन को एक वैध समझौते के रूप में माना जा सकता है जैसा कि एल. ए. अधिनियम की धारा 41 के तहत इस पक्ष में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रदान किया गया है।

लाभार्थी कंपनी का?

अंक संख्या 10

क्या कलेक्टर ने लगभग निर्धारित किया है। प्रावधानों के तहत आवश्यकतानुसार दिए जाने और जमा किए जाने वाले मुआवजे की राशि

एल. ए. अधिनियम की धारा 23 और 24 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया?
मुद्दा नं. 11

क्या कलेक्टर द्वारा एल. ए. अधिनियम की धारा 9,10 और 11 के अनुपालन में पुरस्कार पारित किए जाते हैं और अधिनियम की धारा 12 (2) के तहत आवश्यक पुरस्कार नोटिस जारी किए जाते हैं और मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों को दिए जाते हैं और उसके बाद भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा एल. ए. अधिनियम की धारा 16 के तहत लिया जाता है और कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है?

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

अंक संख्या 12

(ए) क्या इलाके में भूमि अधिग्रहण करने वाली विवादित अधिसूचनाएं कानूनी हैं।

राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23.4.1984 और दो नदियों के अनुसार।
" के अनुसार विचाराधीन भूमि में तुआनई और नाला बह रहे हैं।

वन विभाग द्वारा जारी उपग्रह मानचित्र, क्या यह पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा

और इलाके में पर्यावरण?

और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह वन्यजीव (संरक्षण) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अधिनियम; वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम के साथ-साथ जल
(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

1986 और इस कारण से यह या तो जनहित या जनता को प्रभावित करेगा।

चोट या कानून के शासन का उल्लंघन?

मुद्दा संख्या। 13 , 14 & 15

13. क्या पी. आई. एल. को सफल होना चाहिए यदि प्रश्न संख्या। 12 (ए) और (बी) का जवाब दिया जाता है

अपीलार्थियों के पक्ष में और भूमि के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए
अधिग्रहण अधिनियम और भूमि अधिग्रहण (कंपनी) नियम, 1963

और

14. क्या अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द होने के लिए उत्तरदायी है, यदि

याचिकाकर्ताओं ने इसके द्वारा न्यायिक समीक्षा शक्ति का प्रयोग करके एक मामला बनाया है।

अदालत? और

15. राहत याचिकाकर्ता किसके हकदार हैं?

7. उपरोक्त मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, उच्च न्यायालय ने
अदालत ने संबंधित 15 प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार दिया है:

मुद्दे

(i) में उल्लिखित विवरणों के अनुसार

मुद्दा संख्या 1

19.07.2006 पर दाखिल

किया गया प्रपत्र संख्या 32,

क्या अनिल अग्रवाल

याचिकाकर्ता के पास केवल 3

निदेशक हैं

फाउंडेशन,

लाभार्थी

इसके बोर्ड पर और 7 से कम

द.

कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी है

सदस्य, जो किससे कम है

धारा के तहत परिभाषा की शर्तें

पब्लिक लिमिटेड के लिए
हैं

आवश्यक

की धारा 12 (बी) के तहत कंपनी

3 (1) (4) कंपनी अधिनियम,

1956 और क्या निजी गारंटी दे सकते हैं

कंपनी अधिनियम, 1956।

सीमित कंपनी में परिवर्तित किया जाए

(ii) याचिकाकर्ता ने बदलने की कोशिश

की थी।

धारा 25 के तहत सार्वजनिक कंपनी

निजी से सार्वजनिक तक इसकी

स्थिति

कंपनी अधिनियम?

192

याचिकाकर्ता ने नहीं

और

सार्वजनिक कंपनी की स्थिति।

कंपनी लेकिन वही विषय था
धारा 23,31 का अनुपालन,
189 (2) और कंपनियों के

अधिनियम, 1956।

प्रस्तुत की गई प्रमाणित प्रति
ज्ञापन और लेख
संघ के तहत आवश्यकतानुसार
धारा 31 (2 ए) के प्रावधान

इसलिए प्राप्त नहीं किया था

iii) फाउंडेशन एक धारा 25 है।
कंपनी, और इसलिए एक नहीं
पब्लिक लिमिटेड कंपनी।

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहण।

मुद्दा संख्या 2

सिवाय इसके कि

क्या राज्य सरकार कर सकती है

विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण करें

लाभार्थी कंपनी का पक्ष

(ए) के रूप में

अपने प्रतिष्ठित क्षेत्र का प्रयोग करते हुए

है

एक्ट करें। अतः अधिग्रहण में

उद्देश्य के लिए शक्ति

प्रस्तावित की स्थापना

(i) निजी क्षेत्र के लिए भूमि

कंपनी की अनुमति नहीं है

में उल्लिखित उद्देश्य के लिए

अधिनियम की धारा 40 (1)

धारा 44-बी के तहत कहा गया

सवाल अवैध है।

((ii) विचाराधीन विश्वविद्यालय गैर-विश्वविद्यालय है।

वेदांत

विश्वविद्यालय

अस्तित्व) धारा 44-बी को देखते हुए

कोई विश्वविद्यालय नहीं आया है

विश्वविद्यालय के तहत अस्तित्व

में

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894?

1956 या

के तहत।

जो

अंक संख्या 3

क्या राज्य सरकार

वेदांत की मांग

किया गया, लेकिन

फाउंडेशन शुरू कर सकता था
अधिग्रहण कार्यवाही

जो लाभार्थी कंपनी है।

लाभार्थी कंपनी धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना जारी करके) एल. ए. अधिनियम द्वारा इसका
पालन किए बिना कोई जांच नहीं की गई है।

धारा के अनिवार्य प्रावधान

पढ़ा
भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)

अनुदान आयोग अधिनियम,

उड़ीसा विश्वविद्यालय अधिनियम

(ग) राज्य सरकार ने

एक अध्यादेश जारी किया

एक विश्वविद्यालय स्थापित करें

कानून में असमर्थनीय।

i) धारा 4 (1) के पक्ष में अधिसूचना

लाभार्थी कंपनी थी

माँग के आधार पर किया गया

वेदांत फाउंडेशन द्वारा दायर

के पक्ष में

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन नहीं,

राज्य सरकार के संदर्भ में

नियम-4 को नियम 3 के साथ
है

जाता

39 , 41 और भूमि के 42

अधिग्रहण अधिनियम को नियमों के साथ पढ़ा जाता है

नियम, 1963

3 (2) और भूमि अधिग्रहण का 4) प्रकाशन (कंपनी) नियम, 1963 द्वारा भूमि अधिग्रहण?

धारा 4 (1) में अधिसूचनाएँ

लाभार्थी कंपनी का पक्ष

कारण के लिए कानून में दूषित है

कि प्रावधान रखने से पहले

धारा 4 से 16 और 18 से 37

में

भूमि अधिग्रहण का आदेश जो

पहले नहीं था

राज्य सरकार की सहमति

धारा 39 के तहत वहाँ था और

ऐसी सहमति नहीं दी जाएगी।

जब तक कंपनी ने निष्पादित

नहीं किया है

की धारा 41 के तहत समझौता

अधिनियम।

(iv) धारा 6 के तहत घोषणा में कहा

गया है -

राज्य द्वारा बनाया गया

बिना सलाह के सरकार

भूमि अधिग्रहण समिति

के नियम-3 के तहत गठित किया

जाना

भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)

नियम, 1963।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

(i) अभिलेखों का आदेश पत्रक

मुकदमा संख्या 4

कलेक्टर द्वारा रखे गए खुलासे

) क्या कलेक्टर की आवश्यकता थी

कि कलेक्टर ने नहीं किया है

सार्वजनिक सूचना, बीट के माध्यम से

एक जाँच करें

को

के रूप में

की धारा 5-ए के तहत विचार किया गया

ड्रम, इस तरह के पदार्थ के

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में भी

यहाँ दी जाने वाली अधिसूचना

आपत्तियाँ दर्ज करने की अनुपस्थिति

इलाके में सुविधाजनक स्थान।

कारण दर्शाओ नोटिस के साथ

इसके साथ कोई सूचना नहीं

प्रस्तावित प्रारंभिक अधिसूचना (ii)

भूमि अधिग्रहण करने के लिए

प्रारंभिक अधिसूचना

था।

जारी किया गया और दोनों पर कार्य

किया गया

पक्ष में मालिक/इच्छुक व्यक्ति

के मालिक/इच्छुक व्यक्ति

एक लाभार्थी कंपनी का?

और

) क्या कलेक्टर की आवश्यकता थी

उठ जाते हैं।

राज्य को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए
सरकार. कुछ मामलों में

खंड (1) के अधीन निर्दिष्ट

नियम-4 क्योंकि यह आगे के लिए अनिवार्य है।

एल. ए. की धारा 6 के तहत कार्रवाई

अधिनियम, 1894 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

अधिग्रहण गंभीर होगा

के मालिकों के नागरिक परिणाम

जमीनों पर?

अंक संख्या 5

) चाहे मालिक/इच्छुक हों।

आवश्यकतानुसार अधिग्रहित भूमि
कानून। अतः प्रश्न यह है कि

भूमि द्वारा आपत्तियों को भरना

इच्छुक व्यक्तियों ने नहीं किया

(iii) कलेक्टर ने प्रस्तुत नहीं किया है।

धारा 5-ए के तहत रिपोर्ट

भूमि का अधिनियम या नियम 4

अधिग्रहण (कंपनी) नियम,

1963 .

i) धारा 5 ए के तहत पूछताछ है -

भूमि अनिवार्य है या नहीं

विचाराधीन भूमि के व्यक्तियों के पास है

मालिक आपत्ति करता है

अपने अधिकारों को त्याग दिया या स्वीकार किया

लिखना

इस पर आपत्ति दर्ज नहीं करने के लिए) इस बिंदु का उत्तर नहीं दिया गया है

प्रारंभिक अधिसूचनाएँ?

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा।

और

) क्या कोई देरी हो रही है और

इस कारण वे इसके हकदार नहीं हैं।

राहत के लिए जैसा कि इन रिट में प्रार्थना की गई है

याचिकाएँ?

धारा 6 के तहत घोषणा है -

अंक संख्या 6 और 7

हो चुका है

राज्य द्वारा बनाया गया

क्या कोर कमेटी

बिना सलाह के सरकार

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। में है

भूमि अधिग्रहण समिति

प्रावधान का अनुपालन

के नियम-3 के तहत गठित किया जाना

भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)

धारा 40, की उप धारा (2) के तहत

एल. ए. अधिनियम, 1894 और यह है

नियम, 1963।

एक जांच की और प्रस्तुत किया

राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट। इसके लिए

विचार और अनुपालन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान कर सकते हैं
के नियम 3 और 4 को समाप्त करें भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)
के तहत घोषणा के लिए नियम, 1963 एल. ए. अधिनियम की धारा 6?
और

क्या राज्य सरकार ने

नियम, 1963 और कलेक्टर राज्य को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

समिति को भेजा गया इस उद्देश्य के लिए गठित और

सलाह ली है

घोषणा करने से पहले समिति के तहत अधिसूचित और प्रकाशित भूमि

धारा 6 अधिसूचनाएँ?

23] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

है।

अंक संख्या 8 और 9

(4 ए)।

8. क्या लाभार्थी कंपनी के पास है

निष्पादित किया गया

ज्ञापन

कि है

में से

आवश्यकता के अनुसार समझ

नहीं किया गया

भूमि अधिग्रहण की धारा 41

राज्य सरकार के साथ कार्य करें
कि प्रावधान किया गया है वचन देना

की उप धाराओं (1), (2) और (3) के तहत
अधिनियम की उक्त धारा और

वही आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया जाता है

धारा 42 के तहत आवश्यकतानुसार राजपत्र

वहाँ से?

और

i) समझौता ज्ञापन उप के अनुरूप नहीं

धारा 41 की धारा (1) से

(ii) इसका पालन नहीं किया जाता है।

अधिनियम की धारा 39 जैसा

कोई औपचारिक समझौता लागू

धारा 41 के तहत।

जैसा

9 . क्या ज्ञापन

कंपनी को एक के रूप में माना जा सकता है
वैध समझौता जैसा कि नीचे दिया गया है

एल. ए. अधिनियम की धारा 41 के लिए
विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण

लाभार्थी कंपनी का पक्ष?

दिए जाने वाले मुआवजे

अंक संख्या 10

द्वारा निर्धारित किया गया है

द.

कलेक्टर

है।

क्या

निर्धारित किया गया

की राशि

बिक्री के आधार पर कलेक्टर

लगभग।

दिए जाने वाले मुआवजे और

जिले से प्राप्त आंकड़े

उप-पंजीयक और इसका मूल्य

आवश्यकतानुसार जमा किया गया

प्रावधानों का पालन करते हुए

बिक्री में जमीन दिखाई गई है।

प्रक्रिया जैसा कि नीचे दिया गया है

सांख्यिकी के रूप में माना गया है

एल. ए. अधिनियम की धारा 23 और 24?

बाजार मूल्य और पुरस्कृत

मुआवजे के समान।

i) धारा 9 और 10 के तहत नोटिस

मुद्दा नं. 11
पारित किए जाते हैं

क्या पुरस्कार

किया गया

जारी

द.

नहीं।

को

थे।

मालिकों/इच्छुक व्यक्तियों

अनुपालन में कलेक्टर

एल. ए. अधिनियम की धारा 9,10 और 11

दावा करें

पुरस्कार

बयान

को

मुआवजा नहीं दिया जाता है।

और इसके तहत आवश्यकतानुसार पुरस्कार नोटिस

अधिनियम की धारा 12 (2) जारी की गई है।

(ii) पुरस्कार की सूचना नहीं दी गई

है।

आवश्यकतानुसार भूमि मालिकों

को

और

परोसा जाता है

द.

उस पर

एलए अधिनियम की धारा 12

(2) के तहत

मालिक/इच्छुक

व्यक्तियों और

इसके बाद भूमि का कब्जा

काम करने
जैसा कि धारा 18 के तहत दिया गया है

अपने वैधानिक अधिकारों पर
के लिए

राज्य द्वारा लिया गया है

धारा 16 के तहत सरकार

अधिनियम।

एल. ए. अधिनियम और इसके पक्ष में स्थानांतरित किया गया
कम्पनी?

i) द्वारा जारी किए गए उपग्रह

मानचित्र

अंक संख्या 12

(ए) क्या आक्षेपित अधिसूचनाएँ

द्वारा निर्मित वन विभाग

इलाके में भूमि का अधिग्रहण है

जनहित याचिकाओं में

याचिकाकर्ताओं,

कानूनी और वैध, कुछ भूमि के रूप में

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दो

नदियाँ,

उन्हें वन्यजीवों के लिए घोषित किया जाता है

अर्थात् 'नुआनाल' और 'नाला'

हैं।

राजपत्र के अनुसार अभयारण्य

कुछ अधिग्रहित भूमि में प्रवाह
लाभार्थी के पक्ष में

अधिसूचना दिनांक 23.4.1984 और

कंपनी। अतः नियंत्रण

दो नदियाँ "। नुआनाई "और" नाला "
विचाराधीन भूमि में बह रहे हैं

उक्त नदियाँ इसके अंतर्गत आएंगी

द्वारा जारी उपग्रह मानचित्र के अनुसार

निजी कंपनी ने कहा। अगर

वन विभाग, यह होगा

अधिग्रहण की कार्यवाही

आयोजित की जाती है

कानून में वैध होने के कारण

इलाके में? पारिस्थितिकी और पर्यावरण को प्रभावित करता है

होगा सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत

उल्लंघन किया गया।

(ii) लाभार्थी कंपनी की आवश्यकता

और

उपरोक्त प्रवाह को बनाए रखने

के लिए

((ख) यदि ऐसा है,

क्या यह राशि है

दो नदियाँ भी प्रभावित करेंगी

बड़े पैमाने पर इलाके के

निवासी।

वन्यजीव के प्रावधानों का उल्लंघन

(ii) बड़े पैमाने पर निर्माण

(संरक्षण) अधिनियम; वायु (रोकथाम)

प्रस्तावित की स्थापना

& प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम भी

विश्वविद्यालय भी प्रतिकूल

होगा।

जल के रूप में (रोकथाम और नियंत्रण)

प्रदूषण) अधिनियम और पर्यावरण

वन्यजीव अभयारण्य को

प्रभावित करता है,

1986 का संरक्षण अधिनियम और इसके लिए

संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और

द.

कारण यह या तो प्रभावित करेगा

पारिस्थितिकीय वातावरण में

द.

इलाका।

लोक हित या लोक क्षति या

कानून के शासन का उल्लंघन?

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

i) से अधिग्रहण की कार्यवाही

मुद्दा संख्या। 13 , 14 & 15

प्रारम्भ के चरण की तारीख तक

13. क्या पी. आई. एल. को सफल होना चाहिए यदि

पुरस्कार जो वास्तव में कानून में

नहीं हैं

प्रश्न संख्या। 12 (ए) और (बी) हैं

पुरस्कार दिया गया और कथित

रूप से लिया गया

अपीलार्थियों के पक्ष में जवाब दिया गया

और किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए

अधिक अधिकार का उल्लंघन

किया जाता है

भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम और साथ ही

भूमि अधिग्रहण (कंपनियाँ)

नियम, 1963।

नियम, 1963?

(ii) द्वारा की गई मांग पर

द्वारा लाभार्थी कंपनी

तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत

करना और खेलना

और

राज्य सरकार से धोखाधड़ी,

14. क्या अधिग्रहण की कार्यवाही

है

पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है, यदि

याचिकाकर्ताओं ने एक

मामला, न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करके

किया है

इस न्यायालय द्वारा शक्ति? और

नहीं है

15. राहत याचिकाकर्ता किसके हकदार हैं?

पहुँच

है।

आई. आर. 1995 एससी

पूरी ज़मीन को दूषित कर दिया

अधिग्रहण की कार्यवाही।

(ग) लोकहित के अलावा

याचिकाकर्ताओं ने भी अनुरोध

छोटे भूस्वामियों ने

हाशिए पर पड़ा वर्ग जिनके पास

लड़ने के लिए इस न्यायालय तक

मुकदमेबाजी।

इसलिए, अधिग्रहण

(iv)

कार्यवाही पूरी तरह से उत्तरदायी

निरस्त करने के लिए, के अनुसार

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

एचएमटी हाउस बिल्डिंग में

सहकारी समिति बनाम सैयद

खादर और ओआरएस। , ए.

8. हमने विद्वान वकील को उनकी ओर से उपस्थित होते हुए सुना है

संबंधित पक्ष विस्तार से।

8.1 हमने भी विस्तार से देखा है और विचार किया है

अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को रद्द करने और रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश।

8.2 अब, जहाँ तक अपीलार्थियों की ओर से निवेदन है कि

उच्च न्यायालय ने पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने में गंभीर गलती की है क्योंकि केवल कुछ ही भूमि मालिकों ने प्रस्तुत किया है

अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत आपत्तियाँ और यह कि उच्च न्यायालय ने जनहित का मनोरंजन करने और अनुमति देने में भौतिक रूप से गलती की है

मुकदमे की याचिकाओं का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 के प्रासंगिक प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है और लगभग 7000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। विभिन्न भूमि मालिकों, अर्थात् 6000 परिवारों की कृषि भूमि और इस प्रकार लगभग 30,000 लोगों का विस्थापन शामिल है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लाभार्थी फाउंडेशन/कंपनी/ट्रस्ट के लिए अधिग्रहित भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए वन्यजीव अभयारण्य और [2023] 8 एस. सी. आर. के ठीक बगल में एक प्रमुख स्थान पर किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहण की गई भूमि से राज्य की दो छोटी नदियाँ गुजर रही हैं। जिस तरह से राज्य सरकार ने 6000 परिवारों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया है और वास्तव में यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पक्ष में है,

जिसे बाद में एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था और वह भी आवश्यकता की कोई उचित जांच किए बिना

क्षतिपूर्ति अधिग्रहण कार्यवाही को दरकिनार करने का आधार नहीं हो सकता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया है, अधिनियम, 1894 के तहत वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करने के साथ-साथ नियम, 1963। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की पूरी शुरुआत और यहां तक कि भूमि के चयन से ही कंपनी-लाभार्थी कंपनी द्वारा की गई थी, न कि राज्य द्वारा।

सरकार नियम, 1963 के नियम 4 का पूरी तरह से गैर-अनुपालन है (जिसके बारे में नीचे चर्चा की जाएगी)। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि की है।

जनहित याचिकाओं सहित रिट याचिकाओं पर विचार करना। उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 63 से 67 में जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं पर विचार करते हुए ठोस कारण दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

" 63. ऊपर बताए गए कारणों से, निश्चित रूप से जन-उत्साही व्यक्तियों द्वारा दायर इन रिट याचिकाओं में जनहित शामिल है। यह जानना लाभदायक है कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर क्या फैसला सुनाया।

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन में

भारत सरकार, (1982) 3 एस. सी. सी. 235, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 2 हम अपने आदेश पर पूरे जोर के साथ यह इंगित करना चाहते हैं कि जनहित याचिका जो एक रणनीतिक है

कानूनी सहायता आंदोलन की शाखा और जिसका उद्देश्य गरीब जनता की पहुंच के भीतर न्याय लाना है, जो मानवता के कम दृश्यता क्षेत्र का गठन करते हैं, सामान्य पारंपरिक मुकदमेबाजी से पूरी तरह से अलग तरह का मुकदमा है।

अनिवार्य रूप से एक विरोधी चरित्र जहां दो वादी पक्षों के बीच विवाद है, एक दूसरे के खिलाफ दावा कर रहा है या राहत मांग रहा है और दूसरा इस तरह के दावे का विरोध कर रहा है या ऐसी राहत का विरोध कर रहा है। एल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. के समक्ष जनहित याचिका लाई जाती है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायालय एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरे के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से नहीं है जैसा कि सामान्य मुकदमेबाजी के मामले में होता है, लेकिन इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना और सही साबित करना है जो मांग करता है कि बड़ी संख्या में गरीब, अज्ञानी या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में लोगों के संवैधानिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किसी का ध्यान नहीं जाना चाहिए और उनका निवारण नहीं किया जाना चाहिए। यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा जो सरकार के किसी भी लोकतांत्रिक रूप में सार्वजनिक हित के आवश्यक तत्वों में से एक है। कानून के शासन का मतलब यह नहीं है कि कानून की सुरक्षा केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए या निहित स्वार्थों द्वारा अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को लागू करने की आड़ में यथास्थिति की रक्षा और बनाए रखने के लिए कानून को वेश्यावृत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। गरीबों के पास भी नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं और कानून का शासन उनके लिए भी है, यह सोचते हुए कि आज यह केवल कागज पर मौजूद है और वास्तविकता में नहीं है। अगर चीनी बैरनों और शराब राजाओं को अपना व्यवसाय जारी रखने और उपभोग करने वाली जनता का शोषण करके अपने पर्स को मोटा करने का मौलिक अधिकार है, क्या समाज के सबसे निचले वर्ग के चमारों को अपने पसीने और परिश्रम से ईमानदार जीवन जीने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है? पूर्व में प्रतिष्ठित वकीलों की एक दुर्जेय सेना के साथ अदालतों का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।

प्रतिदिन चार या पाँच अंक और यदि उनके शोषण के अधिकार को मौलिक अधिकार के लेबल के तहत सरकार के खिलाफ बरकरार रखा जाता है, तो अदालतों की उनकी साहस और साहस और उनकी स्वतंत्रता और निर्भीकता के लिए प्रशंसा की जाती है और उनकी सराहना की जाती है। लेकिन, अगर अन्याय के गरीब और असहाय पीड़ितों के मौलिक अधिकार को जनहित याचिका द्वारा लागू करने की कोशिश की जाती है, तो मानवाधिकारों के तथाकथित चैंपियन इसे देश के सर्वोच्च न्यायालय के समय की बर्बादी के रूप में देखते हैं, जो, के अनुसार

उन्हें इस तरह के छोटे और तुच्छ मामलों में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, ये स्वघोषित मानवाधिकार कार्यकर्ता यह भूल जाते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अमूल्य हैं, हमारे लोगों की विशाल जनता के लिए मौजूद नहीं हैं। आज बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हैं जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। वस्तुनिष्ठ गरीबी की स्थितियों में एक उप-मानव अस्तित्व में रहना; पूरी तरह से पीसने वाली गरीबी ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनके नैतिक फाइबर को नष्ट कर दिया है। उन्हें मौजूदा सामाजिक और [2023] 8 एस. सी. आर. में कोई विश्वास नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर्थिक प्रणाली। इन गरीबों के नागरिक और राजनीतिक अधिकार क्या हैं?

और मानवता के वंचित वर्ग लागू करने जा रहे हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रजत जयंती समारोह में डब्ल्यू. पॉल गोर्मसेली द्वारा इसे जबरन सामने लाया गया था:

" चूंकि भारत उन देशों में से एक है जिसने देश में बुनियादी मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं को गौरवपूर्ण स्थान दिया है।

इसका संविधान मौलिक अधिकारों पर अपने अध्याय में और

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर और स्वतंत्रता के पच्चीस साल पहले ही पूरे कर चुके हैं, सवाल

यह उठाया जा सकता है कि मौलिक अधिकार हैं या नहीं

हमारे संविधान में निहित का कोई अर्थ है हमारे लाखों
लोग जिन्हें भोजन, पीने का पानी, समय पर दिया जाता है

चिकित्सा सुविधाएं और बीमारी और आपदा से राहत,

शिक्षा और नौकरी के अवसर अभी भी अपरिहार्य हैं। भारत में हमें इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित और परिभाषित मानवाधिकारों का अध्ययन करना चाहिए और तुलना करनी चाहिए।

व्यवहार में उपलब्ध और हमारे देश के कानून द्वारा सुरक्षित अधिकारों के साथ।

समाज के इन बड़े वर्गों के लिए नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को सार्थक बनाने का एकमात्र समाधान होगा - भौतिक स्थितियों का पुनर्निर्माण करें और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करें ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का एहसास कर सकें। वास्तव में एक ओर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और दूसरी ओर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के बीच घनिष्ठ संबंध है और यह संबंध इतना स्पष्ट है कि 1968 में महासभा द्वारा बुलाए गए तेहरान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन ने एक अंतिम घोषणा में घोषणा की:

" चूंकि मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ हैं

अविभाज्य, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का आनंद लिए बिना असंभव है।

बेशक, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सीमित करने का कार्य ताकि सामाजिक और आर्थिक अधिकार एक लक्ष्य बन जाएं।

गरीब और निम्न वर्गों के लिए सार्थक वास्तविकता समुदाय वह है जो वैध रूप से विधायिका एल
अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. से संबंधित है। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

और कार्यपालिका, लेकिन केवल कार्यपालिका और विधायिका द्वारा सामाजिक और आर्थिक बचाव कार्यक्रमों की शुरुआत

यह पर्याप्त नहीं है और जनहित याचिका सहित बहुआयामी रणनीतियों के माध्यम से ही इन सामाजिक और आर्थिक बचाव कार्यक्रमों को प्रभावी बनाया जा सकता है। जनहित

मुकदमेबाजी, जैसा कि हम इसकी कल्पना करते हैं, अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता, राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण और अदालत की ओर से समुदाय के कमजोर वर्गों को प्रदान किए गए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों का पालन करने और उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए एक सहयोगी या सहयोगी प्रयास है। जिस राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की जाती है, उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए संवैधानिक और कानूनी बुनियादी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में उतनी ही रुचि होनी चाहिए।

वंचित स्थिति, याचिकाकर्ताओं के रूप में जो अदालत के समक्ष जनहित याचिका लाते हैं। जिस राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण को जनहित याचिका में प्रतिवादी के रूप में रखा गया है, उसे वास्तव में इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वह इसे किसी गलत को सुधारने या गरीबों के साथ किए गए अन्याय को दूर करने का अवसर मानता है।

समुदाय के कमजोर वर्ग जिनका कल्याण राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रमुख चिंता है और होनी चाहिए।

एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1982 सी. 149, शीर्ष न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" इसलिए हम यह मानेंगे कि जनता का कोई भी सदस्य

पर्याप्त ब्याज होने पर सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संविधान या कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न सार्वजनिक क्षति के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य के प्रवर्तन और ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के पालन की मांग की जा सकती है। यह कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और संविधान की प्राप्ति की गति को तेज करने के लिए बिल्कुल आवश्यक है।

उद्देश्य "कानून", जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने उर्वरक निगम कामगर संघ बनाम में बताया है। भारत संघ, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 344 ", एक सामाजिक लेखा परीक्षक है और इस लेखा परीक्षा कार्य को तब लागू किया जा सकता है जब वास्तविक लोक हित वाला कोई व्यक्ति अधिकार क्षेत्र को प्रज्वलित करता है। एक अन्य बिंदु जिस पर जोर देने की आवश्यकता है वह यह है कि ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं जहां राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्य या चूक से निस्संदेह सार्वजनिक नुकसान होता है लेकिन ऐसे [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम या चूक किसी व्यक्ति या किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्तियों के समूह के लिए एक विशिष्ट कानूनी क्षति का कारण भी बनती है। ऐसे मामलों में, ए

पर्याप्त रुचि रखने वाला जनता का सदस्य निश्चित रूप से कर सकता है

ऐसे अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली कार्यवाही को बनाए रखना या छोड़ दें "।

जनता दल बनाम के मामले में। एच. एस. चौधरी ने बताया

ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 892, उच्चतम न्यायालय ने एस. पी. गुप्ता (ऊपर) के मामले में किए गए समर्पणों पर ध्यान देते हुए और अपने पहले के निर्णयों को संख्या देते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल एक व्यक्ति जो ईमानदारी से कार्य कर रहा है

पी. आई. एल. की कार्यवाही में पर्याप्त ब्याज अकेले होगा

लोग खड़े हैं और आँसू पोंछने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं

गरीबों और जरूरतमंदों के, उनके उल्लंघन से पीड़ित

मौलिक अधिकार, लेकिन व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या राजनीतिक उद्देश्य या किसी अप्रत्यक्ष विचार के लिए कोई व्यक्ति नहीं। इसी तरह, किसी भी व्यक्तिगत शिकायत को सही साबित करने के लिए अदालत के समक्ष लाई गई रंग या जनहित याचिका के तहत एक परेशान करने वाली याचिका, अस्वीकृति के योग्य है।

सीमा पर।

यह देखना निराशाजनक है कि इस तरह के उतार-चढ़ाव के कारण

अदालतों के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई, अनगिनत दिन हैं

बर्बाद किया गया समय जो अन्यथा खर्च किया जा सकता था

वास्तविकवादियों के मामलों का निपटान। हालाँकि हम नई आविष्कार की गई अवधारणा को बढ़ावा देने और विकसित करने में किसी से पीछे नहीं हैं

पी. आई. एल. और गरीबों के प्रति हमारी सहानुभूति का एक हाथ बढ़ाते हुए,

किसी का ध्यान नहीं गया, प्रतिनिधित्व नहीं किया गया और सुना नहीं गया; फिर भी हम टाल नहीं सकते लेकिन हमारी राय व्यक्त करें कि जबकि वास्तविकवादियों के साथ

सिविल मामलों से संबंधित वैध शिकायत जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति और आपराधिक मामले शामिल हैं जिन व्यक्तियों को अनकही सजा के तहत फांसी की सजा सुनाई गई है

पीड़ा और आजीवन कारावास की सजा पाए और लंबे समय तक कारावास में रखे गए व्यक्ति, अनुचित से पीड़ित व्यक्ति

सरकारी या निजी व्यक्तियों के सेवा मामलों में देरी

कर मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा में जिसमें भारी मात्रा में

सार्वजनिक राजस्व या कर राशि का अनधिकृत संग्रह बंद कर दिया गया, हिरासत में लिए गए लोग हिरासत के आदेशों आदि से अपनी रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं। एल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. के लिए सभी एक लंबी सर्पाकार कतार में खड़े हैं। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

अदालतों में जाने और अपनी शिकायतों का निवारण करने की शौकीन उम्मीद के साथ वर्षों, व्यस्त निकाय, हस्तक्षेप

व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ या अपने लिए या छद्म या दूसरों के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा या प्रचार की चमक के अलावा कोई सार्वजनिक हित नहीं रखने वाले हस्तक्षेप करने वाले, राहगीर या आधिकारिक हस्तक्षेप करने वाले कतार को तोड़ देते हैं।

जनहित का मुखौटा पहनकर उनके चेहरे को ढकना मुकदमेबाजी, और परेशान करने वाली और तुच्छ याचिकाएं दायर करके अदालतों में प्रवेश करें और इस प्रकार आपराधिक रूप से अदालत का मूल्यवान समय बर्बाद करें।

अदालतें और जिसके परिणामस्वरूप अदालत के दरवाजों के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं चलती है, जो तीखी स्थिति वास्तविक वादियों के मन में निराशा पैदा करती है और परिणामस्वरूप वे हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में विश्वास खो देते हैं।

(जोर दिया गया)

इसके अलावा हाल के एक निर्णय में, राज्य तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौपाल और अन्य के मामले में। , में सूचित किया गया

010) 3 एस. सी. सी. 402, उच्चतम न्यायालय ने बड़ी संख्या का उल्लेख किया

इसके पहले के निर्णय इस प्रकार थे:

न्यायालयों ने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ का विस्तार किया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी। का नियम

लोकस स्टैंडी को पतला किया गया था और इसका पारंपरिक अर्थ था

" समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को न्याय तक पहुँच प्रदान करने के लिए पीड़ित व्यक्तियों का विस्तार किया गया था, जिसे अन्यथा न्यायिक प्रणाली से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हम इसे जनहित याचिका का पहला चरण या स्वर्ण युग कहना चाहेंगे। हम विस्तार के बाद पहले चरण में इस अदालत द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण मामलों पर संक्षेप में विचार करेंगे।

"पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा 36. जनहित याचिका प्रतिकूल मुकदमेबाजी की प्रकृति में नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती और एक अवसर है

सरकार और उसके अधिकारी मूल मानवाधिकारों को वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक बनाने के लिए

समुदाय और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय का आश्वासन देना।

जो हमारे संविधान की हस्ताक्षर धुन है। सरकार और उसके अधिकारियों को जनहित याचिका का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें यह जांचने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गरीबों और दलितों को अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल रहे हैं या क्या वे समुदाय के मजबूत और शक्तिशाली वर्गों के हाथों धोखे और शोषण के शिकार बने हुए हैं और क्या वे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। आर्थिक न्याय उनके लिए एक सार्थक वास्तविकता बन गया है या यह केवल एक चिढ़ाने वाला भ्रम और अवास्तविकता का वादा बना हुआ है, ताकि जनहित याचिका में शिकायत सच पाए जाने की स्थिति में, वे अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में शोषण और अन्याय को जड़ से खत्म कर सकें और कमजोर वर्गों को उनके अधिकार और अधिकार सुनिश्चित कर सकें।

39. भारत में जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति से हुआ है।

न्यायपालिका द्वारा समाज के विशाल वर्गों-गरीब और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति। यह

न्यायिक रचनात्मकता और शिल्प कौशल द्वारा क्षेत्राधिकार बनाया और तराशा गया है।

40. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 केवल इस पर शक्ति प्रदान नहीं करता है प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए न्यायालय

मौलिक अधिकार। इसके बजाय, यह लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस न्यायालय पर एक संवैधानिक दायित्व भी रखता है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस संवैधानिक दायित्व को साकार करते हुए, "उसके पास सभी आनुषंगिक और सहायक शक्तियां हैं जिनमें नए उपचार बनाने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तैयार की गई नई रणनीतियां तैयार करने की शक्ति शामिल है।" अदालत ने महसूस किया कि अत्यधिक गरीबी के कारण, समाज के बड़ी संख्या में वर्ग अदालत का रुख नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उनके लिए और उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए कोई अर्थ नहीं है।

न्यायिक नवाचार और रचनात्मकता द्वारा समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के मौलिक अधिकारों को आवश्यक बताते हुए

लोक हित में निर्देश और आदेश पारित करना।

41. जनहित याचिका का विकास भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विकास रहा है।

न्यायशास्त्र। 1970 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने दायर करने की अनुमति देने के लिए सख्त लोकस स्टैंडी आवश्यकताओं को ढीला कर दिया।

समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों की ओर से जन-उत्साही व्यक्तियों, संस्थानों और/या निकायों द्वारा याचिकाएं। उच्च न्यायालयों ने उन्हें शून्य अटल फाउंडेशन ई. टी. सी. के रूप में दी गई व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया। ईटीसी. बी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। किस तरह की जनहित याचिका में न्यायालयों से मांगे गए उपचार प्रभावित व्यक्तियों और समूहों को उपचार देने से परे हैं। उपयुक्त मामलों में न्यायालयों ने दिशा-निर्देश और निर्देश भी दिए हैं। अदालतों ने निगरानी की है

कानून का कार्यान्वयन और यहां तक कि तैयार किए गए दिशानिर्देश भी कानून के अभाव में। यदि 70 और 80 के दशक के मामलों का विश्लेषण किया जाए, तो अधिकांश जनहित याचिका मामले

जिनका न्यायालय द्वारा मनोरंजन किया गया था, वे संबंधित हैं -

हाशिए पर पड़े और वंचित लोगों के मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन

समाज के वर्ग।

यह न्यायालय यह दावा करता है कि वे सार्वजनिक भावना वाले व्यक्ति हैं, कानून में भी इस कारण से असमर्थनीय है कि उन्होंने यह मामला स्थापित किया है कि स्थानीय जनता का हित प्रभावित होगा और यदि अधिग्रहण किया जाता है तो कानून के नियम का उल्लंघन भी होगा। लाभार्थी कंपनी के पक्ष में सरकारी भूमि के संबंध में भूमि और पट्टा अधिकार का अनुदान कानूनी और वैध नहीं माना जाता है और इसलिए हमें यह मानना होगा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में इस न्यायालय की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

राज्य सरकार बहुत पहले वर्ष 1984 में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन कर रही है, जिसमें अधिग्रहित भूमि के आसपास की कुछ भूमि को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज कि दो [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह तर्क कि जनहित याचिका में रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है, कानून में मान्य नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय ने नहीं किया है विचार के लिए उत्पन्न महत्वपूर्ण मुद्दों का जवाब देकर मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया गया। द्वारा वर्तमान रिट याचिकाओं में

स्थायी आधारों का आग्रह करते हुए उन्होंने एक मजबूत मामला बनाया है

राहत देते हैं। यदि पी. आई. एल. याचिकाओं की अनुमति नहीं दी जाती है तो राज्य सरकार और लाभार्थी कंपनी की निरंतर गलती होगी, जो उस इलाके के निवासियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करेगी जहां भूमि का अधिग्रहण किया गया है और भूमि मालिक /

इच्छुक व्यक्ति। वे उन भूमि के छोटे धारक हैं जो संबंधित हैं। समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए और इसलिए उन्हें उस न्याय तक पहुंच नहीं है जिसके लिए उन्हें संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत संवैधानिक अधिकार मिला है और कंपनी के पक्ष में सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि दी गई है जो कानून का पूर्ण उल्लंघन है।

66. पूर्वगामी कारणों से, कंपनी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आग्रह की गई दलीलों में बिल्कुल भी कोई सार नहीं है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर जनहित याचिकाओं के इन मामलों में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है और उन्होंने अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

67. हमने अपने कारणों को दर्ज करके राज्य सरकार और लाभार्थी कंपनी के खिलाफ इन याचिकाओं में बनाए गए सभी बिंदुओं का जवाब दिया है और हमने माना है कि अधिग्रहण दीक्षा के चरण से लेकर कथित शून्य अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. की तारीख तक की कार्यवाही। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

पुरस्कार जो वास्तव में और कानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं और कथित रूप से लिए जाते हैं भूमि अधिग्रहण के भाग-VII के तहत प्रावधानों के साथ पठित धारा 4,5 ए, 6,9,10,11,12, (2), 23,24 के वैधानिक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

अधिनियम, 1894। हमने उन बिंदुओं का भी जवाब दिया है जो जनहित याचिका में हमारे विचार के लिए उठे थे, जिसमें कहा गया था कि वेदांता फाउंडेशन द्वारा की गई मांग पर लाभार्थी कंपनी के पक्ष में अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई थी। तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करने से अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही दूषित हो गई है। हमने आगे जवाब दिया है कि बड़े पैमाने पर जनहित प्रभावित होता है और कानून के शासन का उल्लंघन होता है। इसलिए, हमने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को भी माना है क्योंकि जनहित याचिकाओं को भी अनुमति देने की आवश्यकता है और यह टिप्पणी की है कि उन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने जनहित के अलावा, छोटे भूमि धारकों की ओर से अनुरोध किया है, जिनके पास मुकदमेबाजी लड़ने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए, उन व्यक्तियों के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी तरह से जिनके पास है

इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और यहां तक कि जिन्होंने इस अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है

ए. आई. आर. 1995 एस. सी. सी. 2244 में रिपोर्ट किए गए एच. एम. टी. हाउस बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाम सैयद खादर और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा देखे गए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का घोर उल्लंघन होने के कारण न्यायालय को रद्द किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने विचार के लिए उठाए गए कानूनी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि धारा 44-ए के तहत सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन चूंकि इसका पालन नहीं किया गया है, इसलिए पूरी अधिग्रहण कार्यवाही का पालन किया गया है।

निरस्त कर दिया। इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त में निर्देश दिया

मामला राज्य सरकार और सोसायटी जो कब्जे में थी, कि भूमि का सहारा संबंधित भूमि मालिकों को दिया जाएगा, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या उन्होंने चुनौती दी थी

उनकी भूमि का अधिग्रहण या नहीं और अपने फैसले के पैराग्राफ 25 में नीचे निर्देश दिया गया है:

" 26. हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त अधिसूचना सहित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप, भूमि का कब्जा संबंधित को बहाल किया जाएगा।

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि क्या उनके पास था

उनकी भूमि के अधिग्रहण को चुनौती दी या नहीं। उस पर

भूमि मालिकों को अधिकार की बहाली [2023] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुआवजे के रूप में उनके द्वारा प्राप्त राशि को वापस करें या

अन्यथा उनकी भूमि के संबंध में। अपीलार्थी, उत्तरदाता और सभी सहित राज्य सरकार संबंधित अधिकारी/व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों को जल्द से जल्द लागू करेंगे।

हम रिट याचिकाओं और जनहित याचिकाओं पर विचार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

8.3 जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को यह अभिनिर्धारित करते हुए दरकिनार कर दिया है कि वह गैर-अधिग्रहण द्वारा दूषित है।

अधिनियम, 1894 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन को यहाँ ऊपर संदर्भित और पुनः प्रस्तुत किया गया है।

वेदांत फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत अप्रैल, 2006 के महीने में हुई थी। शुरू में, कंपनी ने उड़ीसा सरकार से विशेष रूप से भुवनेश्वर-पुरी-कोणार्क में पुरी जिले के नुआनाई के आसपास 15,000 एकड़ संलग्न भूमि 15.06.2006 द्वारा उपलब्ध कराने के लिए कहा। प्रक्रिया. उपयुक्त स्थानों की पहचान के लिए कंपनी द्वारा किया गया था। यहां तक कि प्रासंगिक समय पर मुख्यमंत्री को दी गई प्रस्तुति और दिनांक 19.07.2006 के समझौता ज्ञापन के प्रासंगिक खंडों और यहां तक कि उड़ीसा सरकार और अनिल के बीच निष्पादित धारा 41 समझौते से भी।

अग्रवाल फाउंडेशन, यह देखा जा सकता है कि भूमि की पहचान कंपनी द्वारा की गई थी न कि उड़ीसा सरकार द्वारा। ऐसा ही हुआ है।

उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से निपटा गया और उस पर विचार किया गया। 8.5 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अधिग्रहण की कार्यवाही की शुरुआत वेदांत फाउंडेशन द्वारा की गई थी और उसके बाद

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा, जो स्वीकार्य रूप से प्रासंगिक समय पर और 19.07.2006 पर एक निजी कंपनी थी जिसके बोर्ड में तीन निदेशक थे और सात से कम सदस्य थे। अपीलार्थियों की ओर से यह मामला है कि बाद में अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, जो प्रासंगिक समय में एक निजी कंपनी थी, को सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया था

जैसा कि 13.12.2006 पर है, अर्थात्, जिस तारीख को पहली धारा 4 (1) अधिसूचना जारी की गई थी और विचार के लिए प्रासंगिक तारीख 13.12.2006 होगी, उसमें कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा पहचानी गई चिन्हित भूमि के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही की शुरुआत अप्रैल/ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. ए. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. के महीने में हुई थी। ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

जून, 2006, जिसके बाद 19.07.2006 दिनांकित समझौता ज्ञापन हुआ। इसलिए, विचार के लिए प्रासंगिक तिथि 19.07.2006 होगी न कि 13.12.2006 जैसा कि अपीलार्थियों की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए।

8.6 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अन्यथा भी बाद में निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में कथित रूपांतरण

यह अधिनियम, 1894 के तहत वैधानिक प्रावधान से बाहर निकलने का एक प्रयास था। विधि विभाग ने विशेष रूप से कहा कि भूमि नहीं हो सकती है

निजी कंपनी द्वारा उन उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। अधिग्रहण की मांग की गई, उसके बाद ही अपीलकर्ताओं ने कंपनी की स्थिति को निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया। उपरोक्त अपीलार्थियों की ओर से एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास था।

8.7 यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब अपीलार्थी ने अपनी स्थिति को निजी से सार्वजनिक कंपनी में बदलने का प्रयास किया, तो यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 23, 31, 189 (2) और 192 के अनुपालन के अधीन था। जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया और दर्ज किए गए निष्कर्ष और आर. टी. आई. प्रश्न से भी, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने धारा 31 (2 ए) के प्रावधान के तहत आवश्यक संघ के लेखों (संशोधित) की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की। अपीलार्थी की ओर से यह मामला है कि अपीलार्थी सफलतापूर्वक आई. डी. 2 पर सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो गया और इसने सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 कर दी और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 44 के संदर्भ में, उसने शेयरों की निःशुल्क हस्तांतरणीयता पर प्रतिबंध को हटाने के लिए अपने संगठन के अनुच्छेदों में संशोधन किया और इसे कंपनी पंजीयक (आर. ओ. सी.) द्वारा दिनांक आई. डी. 1 और आई. डी. 3 की स्वीकृति द्वारा स्वीकार किया गया है।

संबंधित रूप से, यह नोट किया जाना आवश्यक है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विचार के लिए प्रासंगिक तिथि जून, 2006 होगी और किसी भी मामले में 19.07.2006 जब समझौता ज्ञापन किया गया था। यहाँ तक कि बाद में

आरओसी द्वारा स्वीकृति 21.02.2007 और 03.03.2011 पर भी थी

धारा 4 (1) अधिसूचना के काफी बाद। इसलिए, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया और कानूनी रूप से अभिनिर्धारित किया गया, अपीलार्थी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित नहीं किया गया था, जो कि एक धारा 25 कंपनी थी और इसलिए, एक सार्वजनिक कंपनी नहीं थी। इस स्तर पर अधिनियम, 1894 की धारा 44 बी की आवश्यकता है। जिसे संदर्भित किया जाना है, जो निम्नानुसार है:

“ 44 बी. निजी कंपनियों के लिए कुछ उद्देश्यों को छोड़कर इस भाग के तहत अधिग्रहित नहीं की जाने वाली भूमि

सरकारी कंपनियों की तुलना में। - इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस भाग के तहत कोई भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, सिवाय उप-धारा [2023] 8 एस. सी. आर. के खंड (ए) में उल्लिखित उद्देश्य के।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) धारा 40 की, एक निजी कंपनी के लिए, जो एक नहीं है

सरकारी कंपनी।

स्पष्टीकरण। - " निजी कंपनी "और" सरकारी कंपनी "का अर्थ क्रमशः उन्हें सौंपा जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)। "

8.8 अधिनियम, 1894 की धारा 44 बी के अनुसार, अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, भाग VII के तहत कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि धारा 40 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए, एक निजी कंपनी के लिए जो एक सरकारी कंपनी नहीं है। के अनुसार

स्पष्टीकरण, एक "निजी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 में सौंपा गया है। धारा 39 के साथ पठित धारा 40 (1) के अनुसार, उपयुक्त सरकार की पूर्व सहमति और

समझौता आवश्यक है (धारा 39) और जो तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि

उपयुक्त सरकार को या तो धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत कलेक्टर की रिपोर्ट पर या आयोजित जांच द्वारा संतुष्ट किया जाए, बशर्ते कि अधिग्रहण का उद्देश्य भूमि प्राप्त करना हो।

आवास-कंपनी द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए या सीधे उससे जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए धरा। धारा 39 और 40 निम्नानुसार है:

" 39. उपयुक्त सरकार की पूर्व सहमति और

आवश्यक समझौते का निष्पादन। - धाराओं के प्रावधान 6 16 (दोनों समावेशी) और धारा 18 से 37 (दोनों समावेशी) के तहत किसी भी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए लागू नहीं किया जाएगा।

यह भाग, जब तक कि उपयुक्त की पूर्व सहमति के साथ नहीं

सरकार, जब तक कि कंपनी ने निष्पादित नहीं किया होगा

इसके बाद उल्लिखित समझौता।

40. पिछली पृष्ठताछ। - (1) ऐसी सहमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उपयुक्त सरकार रिपोर्ट पर संतुष्ट न हो जाए।

धारा 5 ए, उप-धारा (2) के तहत या जांच द्वारा कलेक्टर का

जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, -

(क) कि अधिग्रहण का उद्देश्य भूमि प्राप्त करना है।

द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए आवासों के निर्माण के लिए

कंपनी या सीधे सुविधाओं के प्रावधान के लिए

उससे जुड़ा हुआ है, या
(क) कि इस तरह के अधिग्रहण की आवश्यकता किसी ऐसी कंपनी के लिए किसी भवन या काम के निर्माण के लिए है जो लगी हुई है या ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. ए. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. है।
ईटीसी. वी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

किसी भी उद्योग या कार्य में खुद को शामिल करने के लिए कदम उठा रहा है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए है, या

(ख) कि किसी कार्य के निर्माण के लिए इस तरह के अधिग्रहण की आवश्यकता है, और इस तरह के कार्य के लिए उपयोगी साबित होने की संभावना है

जनता को।

(2) ऐसी जाँच ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी और

ऐसा समय और स्थान जो उपयुक्त सरकार

नियुक्त करें।

(3) ऐसा अधिकारी गवाहों को बुला सकता है और उनकी उपस्थिति को लागू कर सकता है और उनके द्वारा दस्तावेजों को पेश करने के लिए मजबूर कर सकता है।

समान साधन और, जहाँ तक संभव हो, उसी तरीके से जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा प्रदान किया गया है।

दीवानी अदालत का मामला "।

8.9 इस प्रकार, प्रासंगिक समय पर, जब कंपनी एक निजी कंपनी थी

कंपनी, धारा 44-बी के तहत प्रतिबंध को देखते हुए, विचाराधीन भूमि को अपीलार्थी द्वारा अधिग्रहित/अधिग्रहित करने की मांग नहीं की जा सकती थी

अधिनियम, 1894 की धारा 40 (1) (क) के साथ पठित धारा 44 ख। इसलिए, उच्च न्यायालय ने ठीक ही माना है कि अधिग्रहण उपरोक्त आधार पर अवैध था।

8.10 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रासंगिक समय पर भी, विचाराधीन विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं था/है क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय ने ऐसा नहीं किया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत और न ही ओरिसा विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत अस्तित्व में आता है। अपीलार्थी की ओर से यह मामला कि राज्य विधानमंडल ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहले ही एक विधेयक पारित कर दिया है, अपीलार्थी के जवाब के अनुसार न तो यहाँ है और न ही वहाँ है,

वही राज्यपाल की मंजूरी के लिए लंबित है।

8.11 यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी अंक संख्या 3 पर विशिष्ट निष्कर्ष दिए हैं कि पूरी अधिग्रहण कार्यवाही लाभार्थी के पक्ष में है।

कंपनी अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी करके

नियम, 1963 के नियम 3 (2) और (4) के साथ पठित अधिनियम, 1894 की धारा 39,40 और 41 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना। नियम, 1963 के नियम 3 और 4 इस प्रकार हैं:

" 3. भूमि अधिग्रहण समिति। - (1) इस उद्देश्य के लिए

अधिग्रहण के संबंध में उपयुक्त सरकार को सलाह देना

अधिनियम के भाग VII के तहत भूमि का, उपयुक्त सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा।

जिसे भूमि अधिग्रहण समिति कहा जाए।

सी आरा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) समिति में शामिल होंगे -
राजस्व, कृषि और उद्योग विभागों के सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी

(i) सरकार के

उपयुक्त सरकार के रूप में उक्त विभागों में से प्रत्येक

((ख) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें उपयुक्त सरकार नियुक्त कर सकती है, ऐसी अवधि के लिए जो वह सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, और ((ग) विभाग का सचिव या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो उन उद्देश्यों के लिए कार्य करता है जिनके लिए कंपनी कार्य करती है।

भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव।

(3) उपयुक्त सरकार समिति के सदस्यों में से एक को अपना अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(4) समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम के भाग VII के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर उपयुक्त सरकार को सलाह दे।

बशर्ते कि उपयुक्त सरकार समिति द्वारा इस संबंध में किए जा रहे अनुरोध पर और पर्याप्त के लिए कारण उक्त अवधि को दो महीने से अधिक की अवधि तक बढ़ाते हैं।

4. अधिग्रहण शुरू करने से पहले कुछ मामलों के संबंध में उपयुक्त सरकार को संतुष्ट होना चाहिए

कार्यवाही। - (1) जब भी कोई कंपनी किसी भूमि के अधिग्रहण के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन करती है, तो वह सरकार कलेक्टर को निम्नलिखित मामलों पर उसे एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगी, अर्थात्:

(i) कि कंपनी ने अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त इलाके में भूमि का पता लगाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है; ((ख) कंपनी ने उचित मूल्य के भुगतान पर उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करके ऐसी भूमि प्राप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास विफल रहे हैं; शून्य अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. बी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

(iii) कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के लिए उपयुक्त है

उद्देश्य;

(iv) कि अधिग्रहित करने के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र नहीं है।

(v) कि कंपनी भूमि का शीघ्रता से उपयोग करने की स्थिति में है; और
(vi) जहां अधिग्रहित की जाने वाली भूमि अच्छी कृषि भूमि है, वहां कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थान नहीं मिल सकता है ताकि -

उस भूमि के अधिग्रहण से बचें।

(2) कलेक्टर कंपनी को एक

इस संबंध में कोई अभ्यावेदन देने का उचित अवसर, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मामलों की जांच करना और
ऐसी जांच करते समय वह -

(i) किसी भी मामले में जहां अधिग्रहित की जाने वाली भूमि कृषि भूमि है, जिले के वरिष्ठ कृषि
अधिकारी से परामर्श करें कि क्या ऐसी भूमि अच्छी कृषि भूमि है या नहीं।

(iii) यह पता लगाने के लिए कि क्या कंपनी ने उचित मूल्य (इस प्रकार निर्धारित मुआवजे से कम
नहीं होने के कारण) की पेशकश की है।
अधिग्रहण की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति।

स्पष्टीकरण। - इस नियम के प्रयोजन के लिए "अच्छी कृषि भूमि" का अर्थ है कोई भी भूमि जो कृषि के स्तर
को देखते हुए जिस क्षेत्र में यह स्थित है, उसका उत्पादन और फसल का स्वरूप औसत या औसत
उत्पादकता से अधिक है और इसमें एक उद्यान या उपवन भूमि शामिल है।

(3) उप-नियम (2) के तहत जांच करने के बाद कलेक्टर जितनी जल्दी हो सके, उपयुक्त को एक रिपोर्ट
प्रस्तुत करेगा।

सरकार और उसकी एक प्रति उस सरकार द्वारा समिति को भेजी जाएगी।

(4) अधिनियम की
धारा 6 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा तब तक कोई घोषणा नहीं की जाएगी जब तक कि-[2023] 8 एस.
सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) उपयुक्त सरकार ने समिति से परामर्श किया है। और इस नियम के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट और अधिनियम की धारा 5-ए के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार किया है; और

((ii) अधिनियम की धारा 41 के तहत समझौते को लागू कर दिया गया है।

कम्पनी द्वारा "।

8.12 प्रासंगिक समय पर, कोई धारा 41 समझौता नहीं था

सभी। यहां तक कि राज्य सरकार द्वारा नियम, 1963 के नियम 3 के साथ पठित नियम 4 के संदर्भ में भी कोई जांच नहीं की गई थी। राज्य सरकार द्वारा नियम, 1963 के नियम 3 के तहत गठित की जाने वाली भूमि अधिग्रहण समिति से परामर्श किए बिना धारा 6 के तहत घोषणा जारी नहीं की जा सकती थी। राज्य सरकार द्वारा कोर समिति का गठन, जिसे पूरे अधिग्रहण का समन्वय करना था, को नियम 3 के तहत आवश्यक भूमि अधिग्रहण समिति का गठन नहीं कहा जा सकता है। नियम 3 के तहत भूमि अधिग्रहण समिति के गठन का उद्देश्य और उद्देश्य अधिनियम, 1894 के भाग 7 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले सभी मामलों पर उपयुक्त सरकार को सलाह देना और अपनी सलाह देना है। इसलिए इस जमीन पर

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को भी बाधित कर दिया गया है। 8.13 नियम, 1963 के नियम 4 के तहत अनिवार्य आवश्यकता का गैर-अनुपालन है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने से पहले

कंपनी के लिए, सरकार कलेक्टर को नियम 4 में उल्लिखित मैट्स पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देगी, जिसमें शामिल हैं:

" (i) कि कंपनी ने अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त इलाके में भूमि का पता लगाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है;

((ख) कंपनी ने उचित मूल्य के भुगतान पर उसमें रुचि रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत करके ऐसी भूमि प्राप्त करने के लिए सभी उचित प्रयास किए हैं और ऐसे प्रयास विफल रहे हैं;

(v) कि कंपनी भूमि का शीघ्रता से उपयोग करने की स्थिति में है; और
(vi) जहां अधिग्रहित की जाने वाली भूमि अच्छी कृषि भूमि है, वहां कोई वैकल्पिक उपयुक्त स्थान नहीं मिल सकता है ताकि इससे बचा जा सके।

उस भूमि का अधिग्रहण "। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

8.14 नियम 4 (2) (i) के अनुसार किसी भी मामले में जहां अधिग्रहित करने के लिए प्रस्तावित भूमि कृषि भूमि है, कलेक्टर से परामर्श करने की आवश्यकता है

जिले के वरिष्ठ कृषि अधिकारी चाहे ऐसी भूमि अच्छी कृषि भूमि हो या नहीं। कलेक्टर को अधिनियम की धारा 23 और 24 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, भूमि के संबंध में देय मुआवजे की अनुमानित राशि को संतुष्ट करना और निर्धारित करना भी आवश्यक है, जो कलेक्टर की राय में,

कंपनी के लिए अधिग्रहण। 8.15 अभिलेख पर मौजूद सामग्री से, उच्च न्यायालय ने विशिष्ट निष्कर्ष दिए हैं कि अनिवार्य प्रावधानों का गैर-अनुपालन है

नियम, 1963 के नियम 3 और 4 के तहत और इसलिए, लाभार्थी कंपनी के लिए पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दूषित कर दिया गया है और नियंत्रण और संतुलन और कुछ अनिवार्य प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना है, विशेष रूप से, जब कंपनी के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, तो उनका पालन करना होगा और प्रासंगिक पहलुओं पर विचार नहीं करना होगा, जो अनिवार्य हैं

नियम 4 में उल्लिखित है। 8.16 यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि लाभार्थी कंपनी ने आवश्यकता के अनुसार समझौता ज्ञापन को निष्पादित नहीं किया है

अधिनियम की धारा 41 के तहत जो राज्य सरकार धारा 41 की उप-धाराओं (1), (2) और (3) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भी करती है। ऐसा आदेश देते हुए, पैराग्राफ 53 में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

" 53. इसके अलावा जैसा कि राज्य सरकार के मूल अभिलेखों से देखा जा सकता है कि प्रारंभिक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। और वेदांत फाउंडेशन और लाभार्थी कंपनी से समझौते प्राप्त करना भी कानूनी रूप से खराब है क्योंकि हम

बिंदु नहीं का जवाब दिया है। 1 अभिनिर्धारित करना कि लाभार्थी कंपनी यह एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है; यह गारंटी द्वारा सीमित एक निजी कंपनी है। अपनी निजी कंपनी में भूमि का आगे अधिग्रहण

गारंटी द्वारा सीमित। इसके पक्ष में भूमि अधिग्रहण की अनुमति केवल कंपनी द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए आवास निर्माण के उद्देश्य या प्रावधान के संबंध में है।

उससे सीधे जुड़ी सुविधाएं।

वेदांता कंपनी द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित दिनांक 1 का समझौता ज्ञापन (2023) 8 एस. सी. आर. को प्रकाशित करने से पहले था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिग्रहित भूमि के संबंध में प्रारंभिक अधिसूचनाएँ। उक्त समझौता ज्ञापन की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 13.12.2006 के आधार पर 22.12.2006 को प्रकाशित किया गया था। इसलिए, उक्त समझौते को लाभार्थी कंपनी द्वारा LA.Act की धारा 39 के तहत प्रदान की गई पूर्व सहमति देकर धारा 4 (1) अधिसूचनाओं को प्रकाशित करने के लिए राज्य सरकार के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया था।

प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए पूर्व सहमति के लिए इस कारण, वेदांत कंपनी द्वारा निष्पादित उक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक अधिसूचनाओं का प्रकाशन लाभार्थी कंपनी के लाभ के लिए सुनिश्चित नहीं है। अतः उक्त

समझौता धारा 39 के तहत आवश्यक रूप से मान्य नहीं है।

आई. डी. 1 की धारा 41 और इसलिए, लाभार्थी कंपनी के पक्ष में धारा 4 (1) अधिसूचना प्रकाशित करके भूमि अधिग्रहण को कानून में इस कारण से दूषित किया जाता है कि

धारा 4 से 16 और 18 से 37 के प्रावधानों में लाभार्थी कंपनी के पक्ष में भूमि अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार की कोई पूर्व सहमति नहीं थी और ऐसी सहमति भी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि कंपनी ने LA.Act की धारा 41 के संदर्भ में समझौते को निष्पादित नहीं किया है। इसलिए, समझौता केवल नहीं है

धारा 41 की उप-धारा (1) से (4) और (4 ए) के अनुरूप नहीं है, लेकिन यह इस कारण से वैध और वैध नहीं है कि उक्त समझौते से बहुत पहले, प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

और उसके बाद अंतिम अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं जो नहीं हैं

कानून में अनुमति। इसलिए, वही उल्लंघन में है

अधिनियम की धारा 39 "।

8.17 सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जिसे पर्यावरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न करने और अधिग्रहित भूमि से दो नदियों के गुजरने पर विचार करने की आवश्यकता है। यह विवाद में है कि विचाराधीन भूमि से दो नदियाँ नामतः 'नुआनई' नाला 'बह रहे हैं', जिन्हें राज्य द्वारा अधिग्रहित किया गया था

आरएनमेंट। नदियों आदि का रखरखाव कैसे किया जा सकता है।

लाभार्थी कंपनी को। यदि विचाराधीन भूमि जारी रहती है

लाभार्थी कंपनी द्वारा अधिग्रहित, नदियों का नियंत्रण

उक्त निजी कंपनी के साथ होगा, जो डॉक्ट्रिन ब्लिक ट्रस्ट का उल्लंघन करेगी। यहां तक कि लाभार्थी कंपनी को ए. एन. आई. एल. ए. जी. ए. आर. डब्ल्यू. ए. एल. फाउंडेशन ई. टी. सी. बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ईटीसी. बी.

ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

ऊपर की दो नदियों का प्रवाह भी बड़े पैमाने पर इलाके के निवासियों को प्रभावित कर सकता है।

8.18 यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सड़क के ठीक पार, एक वन्यजीव अभयारण्य है, जो सड़क के ठीक बगल में है।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय और अधिग्रहित भूमि। इसलिए, उच्च न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण से वन्यजीव अभयारण्य, संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली और इलाके के पारिस्थितिक पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वन्यजीव अभयारण्य की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और इलाके के पारिस्थितिक पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रस्तावित वेदांत विश्वविद्यालय से समुद्र की दूरी भी लगभग 2000 मीटर है। सिर्फ इसलिए कि बालूखंड

वन्यजीव अभयारण्य को प्रस्तावित स्थल से राजमार्ग-पुरी-कोणार्क मरीन ड्राइव द्वारा अलग किया गया है, प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए विशाल भूमि का अधिग्रहण करने का आधार नहीं हो सकता है और जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, यह वन्यजीव अभयारण्य और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और इलाके के पारिस्थितिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए के तहत प्रस्ताव और/या आपत्तियों पर विचार करते समय भी राज्य सरकार और/या कलेक्टर और/या उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

8.19 अन्यथा भी, लाभार्थी द्वारा भूमि की आवश्यकता पर राज्य सरकार की ओर से एक गैर-आवेदन है।

कंपनी। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि भूमि का अधिग्रहण एक फाउंडेशन/कंपनी के कहने पर प्रस्तावित किया गया था और राज्य सरकार कृषि से संबंधित भूमि का सौदा कर रही थी।

लाभार्थी/न्यास। अन्य सार्वजनिक न्यास/कंपनियाँ भी हो सकती हैं, जो इस तरह के विश्वविद्यालय की स्थापना में रुचि ले सकती हैं। ऐसा लगता है कि सरकार/कलेक्टर द्वारा भी कोई उचित जांच शुरू नहीं की गई है।

लाभार्थी कंपनी के प्रस्ताव पर विचार करना। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि शुरू में, प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए 15,000 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी। अंततः, निजी भूमि मालिकों/कृषि से संबंधित लगभग 8000 एकड़ भूमि

जमींदारों का अधिग्रहण किया गया। राज्य सरकार ने भी [2023] 8 एस. सी. आर. सौंपे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.20 अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह प्रतीत होता है कि अनुचित लाभ प्रस्तावित किए गए थे/वास्तव में प्रस्तावित किए गए थे और लाभार्थी कंपनी को दिए गए थे अनुचित उदारता प्रदान करना जैसे कि:

वेदांत विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों को पूर्ण स्वायत्तता

(i)

प्रशासन, प्रवेश, शुल्क संरचना, पाठ्यक्रम के संबंध में

और संकाय चयन;

((ख)

प्रस्तावित विश्वविद्यालय को किसी से भी पूर्ण प्रतिरक्षा होगी

राज्य सरकार के आरक्षण कानून;

(iii) यू. जी. सी. से नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में सभी सहायता,

ए. आई. सी. टी. ई. आदि ;

(@ (iv) सरकार 4 लेन की सड़क प्रदान करने पर सहमत हुई।

प्रस्तावित स्थल पर भुवनेश्वर शहर;

समझौते में, सरकार ने भी करने पर सहमति व्यक्त की

(v)

वेदांत के साथ परामर्श के बाद ही विश्वविद्यालय की सीमा से 5 किमी के दायरे में भूमि उपयोग/क्षेत्र निर्धारण योजना;

(vi) सरकार ने सभी राज्य शुल्कों/करों/शुल्कों को छूट देने का भी वादा किया। आर एंड डी उपकरण, शैक्षणिक सहायता, प्रयोगशाला उपकरण और उपकरण, और निर्माण सामग्री पर वैट, कार्य अनुबंध कर, स्टाम्प शुल्क और प्रवेश कर

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि;

(vii) सरकार ने एस. पी. सी. बी. से एन. ओ. सी. प्राप्त करने और फाउंडेशन से सभी मंजूरी प्राप्त करने में फाउंडेशन की सहायता करने का भी वादा किया।

केंद्र सरकार;

(viii) सरकार ने फाउंडेशन की सहायता करने का भी वादा किया।

परियोजना के लिए तेजी से ई. आई. ए. और ई. एम. पी. की व्यवस्था करना;

(ix)

सरकार ने असाधारण रूप से बड़ी राशि प्रदान करने का भी वादा किया

बिजली और पानी की मात्रा।

8.21 यह सराहनीय नहीं है कि सरकार ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया

एक न्यास/कंपनी के पक्ष में अनुचित पक्ष। इस प्रकार, पूरी अधिग्रहण कार्यवाही और लाभ, जो राज्य द्वारा प्रस्तावित किए गए थे

पक्षपात और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से सरकार दूषित हो गई थी।

अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ई. टी. सी. ईटीसी. वी. ओडिशा और ओ. आर. एस. का राज्य। [एम. आर. शाह, जे.]

8.22 उपरोक्त और उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए विस्तृत निष्कर्षों से हम संतुष्ट हैं कि

उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है और वास्तव में उच्च न्यायालय को पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को दरकिनार करने में उचित ठहराया गया था, जिसे अधिनियम, 1894 और नियम, 1963 के तहत वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से दूषित किया गया है और दुर्भावना और पक्षपात से दूषित किया गया है और यह प्रासंगिक पहलुओं पर दिमाग के गैर-अनुप्रयोग का एक स्पष्ट मामला है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

8.23 अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन कि अब अपीलार्थी केवल 3837 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तक ही सीमित रहने के लिए तैयार है और अब वे 7 भूमि हारने वालों, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की हैं, की भूमि को अधिग्रहण कार्यवाही से और/या इस न्यायालय के समक्ष भूमि मालिकों और/या इस न्यायालय के समक्ष भूमि हारने वालों की भूमि से बाहर रखने के लिए तैयार हैं, यह हमारे निष्कर्ष को मजबूत करेगा कि

आवश्यकता के संबंध में कोई उचित जांच नहीं थी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, शुरू में 15,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, जो अब घटकर 3837 एकड़ रह गया है। अर्थात्, प्रस्ताव अतिशयोक्तिपूर्ण मांग के लिए था। यह अपीलार्थी कंपनी/फाउंडेशन की ओर से दुर्भावनापूर्ण इरादा था। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं, विशेष रूप से जनहित याचिका याचिकाकर्ताओं की ओर से विशिष्ट मामला था कि यदि इतनी बड़ी भूमि का अधिग्रहण किया गया होता और/या यहां तक कि भूमि, जो पहले से ही अधिग्रहित की गई होती, तो इसका दुरुपयोग किया जाता और/या खनन गतिविधियों आदि जैसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है

कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि 6000 परिवारों की कृषि भूमि है और उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि भूमि पर है, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है, इसलिए अब किए गए प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, ये सभी अपील विफल हो जाती हैं और वे खारिज किए जाने के योग्य हैं और तदनुसार हैं।

लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा रु। 5 अपीलार्थी-लाभार्थी कंपनी-अनिल अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के पंजीयक के पास जमा किए जाने वाले लाख और इस तरह की जमा राशि को उड़ीसा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाए।

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।

बिभूति भूषण बोस

(सहायक: राहुल राठी, एलसीआरए)